

भारत पर भी डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे टैरिफ

एजेंसी। टारंटो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन सहित अन्य देशों द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने की आलोचना की और इसे बेहद अनुचित करार दिया। ट्रंप ने साथ ही घोषणा की कि अगले महीने से जवाबी शुल्क लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति ने जवाबी शुल्क को लेकर अपना पक्ष रखा और कहा कि दो अप्रैल से लागू जाएंगे। वह अन्य देशों से आयात पर वही शुल्क लगाना चाहते हैं, जो वे देश अमेरिका से होने वाले निर्यात पर लगाते हैं। ट्रंप ने मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। यह व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल

का पहला संबोधन था। इस साल 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कहा, अन्य देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ शुल्क लगाए हैं और अब हमारी बारी है कि हम उन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। औसतन, यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा क्या आपने उनके बारे में सुना है और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत अधिक टैरिफ वसूलते हैं, जितना हम उनसे वसूलते हैं, ट्रंप ने कहा। यह बहुत अनुचित है। भारत हमसे 100 प्रतिशत से अधिक ऑटो टैरिफ वसूलता है। फरवरी में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन जल्द भारत



वाशिंगटन में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

और चीन जैसे देशों पर जवाबी शुल्क लगाएगा, उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान भी यह कहा था। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अमेरिका के

जवाबी शुल्क से नहीं बख्शा जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि शुल्क संरचना पर कोई भी उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, हमारे उत्पादों पर चीन का औसत शुल्क दोगुना है और दक्षिण कोरिया का

औसत शुल्क चार गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, चार गुना ज्यादा और हम दक्षिण कोरिया को सैन्य रूप से तथा कई अन्य तरीकों से इतनी मदद देते हैं। लेकिन यही होता है। यह दोस्त और दुश्मन दोनों की तरफ से हो रहा है। यह प्रणाली अमेरिका के लिए उचित नहीं है।

ट्रंप ने कहा। हमें लगभग हर देश ने दशकों तक लूटा है, और हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उचित नहीं है। पारस्परिक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे। वे हम पर या अन्य देशों पर जो भी टैरिफ लगाएंगे, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। यह पारस्परिक है। इस दौरान रिपब्लिकन

संसदों खूब तालियां बजायीं। यदि वे हमें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए गैर-मौद्रिक टैरिफ लगाते हैं, तो हम उन्हें अपने बाजार से बाहर रखने के लिए गैर-मौद्रिक अवरोध लगाएंगे। इसमें बहुत कुछ है। वे हमें अपने बाजार में आने की अनुमति भी नहीं देते हैं। हम खरबों डॉलर लेंगे और ऐसी नौकरियां पैदा करेंगे, जैसी हमने पहले कभी नहीं देखीं। मैंने चीन के साथ ऐसा किया, और मैंने दूसरों के साथ भी ऐसा किया और बिडेन प्रशासन इसके बारे में कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह इतना पैसा था कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। मैक्सिको और कनाडा दोनों के साथ अमेरिका का घाटा बहुत बड़ा है। लेकिन इससे भी (शेष पृष्ठ 9)



सीबीआई ने बोफोर्स मामले में अमेरिका से मांगी जानकारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सीबीआई ने हर्शमैन की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज और यदि उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो उसकी जानकारी लेने के लिए वित्त मंत्रालय से भी संपर्क किया, लेकिन उस समय के रिकॉर्ड एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराए जा सके। एजेंसी ने कई साक्षात्कारों में हर्शमैन के दावों पर ध्यान दिया और 2017 में घोषणा की कि मामले को उचित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी। इस पत्र अनुरोध की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 8 नवंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 13 मई 2024 और 14 अगस्त 2024 को अमेरिकी अधिकारियों को भेजे गए पत्रों और रिमाइंडर से कोई जानकारी नहीं मिली।

पत्र अनुरोध एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत किसी आपराधिक मामले को जांच या अभियोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की अदालत को भेजती है। इंटरपोल को किए गए अनुरोधों का भी कोई नतीजा नहीं निकला। एजेंसी ने विशेष न्यायालय को सूचित किया, जिसने 11 फरवरी को सीबीआई के एलआर आवेदन को मंजूरी दे दी। यह अनुरोध किया जाता है कि माइकल हर्शमैन द्वारा उपर्युक्त साक्षात्कार में किए गए दावों से संबंधित तथ्य का (शेष पृष्ठ 9)

कनाडा ने अमेरिका के व्यापार युद्ध की निंदा की

एजेंसी। टारंटो

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को अमेरिकी शुल्क को बेहद मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू करते हुए रूस को खुश कर रहे हैं। ट्रूडो ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कनाडा ट्रंप के 25 प्रतिशत शुल्क के जवाब में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाएगा। आज अमेरिका ने अपने सबसे करीबी साथी और सहयोगी कनाडा खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू कर दिया। साथ ही, वे रूस के साथ सकारात्मक रूप से काम करते, झूठ बोलने वाले हत्यारे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को बुधवार को यह बात कर रहे हैं। ट्रंप ने वाशिंगटन के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों मैक्सिको, कनाडा और चीन के खिलाफ शुल्क लगाया, जिसके कारण इन तीनों देशों ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। ट्रूडो ने गुस्से में आरोप लगाया कि ट्रंप कनाडाई अर्थव्यवस्था का पूरी तरह पतन चाहते हैं, क्योंकि इससे कनाडा को अमेरिका में मिलाना आसान हो

जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम कभी भी 51वें राज्य नहीं बनेंगे। बाद में मंगलवार को अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने नरमी के संकेत देते हुए कहा कि शुल्क को रोकना नहीं जाएगा, लेकिन ट्रंप कुछ समझौता कर लेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि ट्रूडो ने मंगलवार दोपहर को कनाडा के प्रांतों के प्रधानमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें बुधवार को ट्रंप से बात करने की उम्मीद है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल से सहमत होना मेरी आदत में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड, वे बताते हैं कि भले ही आप बहुत होशियार व्यक्ति हों, लेकिन ऐसा करना बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। मंगलवार को बाद में, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिका कनाडा और मैक्सिको से बीच में मिल सकता है, जिसकी घोषणा बुधवार को ही की जाएगी। लुटनिक ने फॉक्स बिजनेस न्यूज को बताया कि टैरिफ को रोकना नहीं जाएगा, लेकिन ट्रंप समझौता कर लेंगे। लुटनिक ने कहा उन्हें लगता है कि वह समझ जाएगा, आप और अधिक करें, और मैं किसी तरह बीच में आपसे मिलांगा। (शेष पृष्ठ 9)

चीन ने बढ़ाया रक्षा बजट, भारत के लिए चुनौती

एजेंसी। बीजिंग

चीन ने बुधवार को अपने राष्ट्रीय रक्षा बजट में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जो इस वर्ष बढ़कर कुल 249 बिलियन अमेरिकी डॉलर (21,68,043 करोड़ रुपये) का होगा। यह घोषणा सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए अपने नवीनतम प्रयासों के बीच की गई, जिसमें युद्धपोतों और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का तेजी से विकास शामिल है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा चीन को संसद को प्रस्तुत मसौदा बजट रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष देश के लिए निर्भोजित रक्षा व्यय 1.784665 ट्रिलियन युआन (लगभग 249



चीन के बीजिंग में वेंग होल ऑफ द पीपल में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) के उद्घाटन सत्र के दौरान तालियां बजाते चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग।

बिलियन अमेरिकी डॉलर) है। पिछले वर्ष की तुलना में चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे लगभग 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.67 ट्रिलियन युआन) कर दिया।

वरिष्ठ आईपीएस अफसर की बेटी सोने की तस्करी में पकड़ी गयी

पायनियर समाचार सेवा। बेंगलुरु

कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के पास से 14.2 किलोग्राम सोने की छड़ें जब की गईं हैं, जिनका अनुमानित मूल्य 12.56 करोड़ रूप है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभिनेत्री रान्या राव भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद पर हैं।



दुबई से बेंगलुरु पहुंची थी। जांच करने पर, उनके पास 14.2 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ें पाई गईं, जिन्हें छिपा कर रखा हुआ था। राजस्व खुफिया निदेशालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्रालय के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत 12.56 करोड़ रूप मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई। इस कार्रवाई के बाद, डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु के लावेल रोड स्थित केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक यात्री के पास से 12.56 करोड़ रूप मूल्य की सोने की विदेशी छड़ें जब्त कीं। खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीआरआई अधिकारियों ने 33 वर्षीय एक भारतीय महिला यात्री को रोकें, जो तीन मार्च को एमिरेट्स (एयरलाइंस) की एक उड़ान से

घरेलू सहायिका के वेश में काम करने वाली नक्सली महिला गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की उपराध शाखा ने एक नक्सली महिला को पीतमपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला अपनी पहचान छुपा कर यहां घरों में घरेलू सहायिका का काम करती थी। 23 वर्षीय महिला नक्सली मूल रूप से पूर्वी राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के कुदाबुर गांव की रहने वाली है। वह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के कई मामलों में बांछित थी। नक्सली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। झारखंड की एक अदालत ने 26 मार्च 2023 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस ने बताया कि महिला नक्सली संघर्ष: वर्ष 2020 में दिल्ली आई थी। वह अपनी पहचान छुपा कर नोएडा और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घरेलू सहायिका के रूप में काम रही थी। बाद में वह पीतमपुरा में रहने लगी। पुलिस उपयुक्त (अपराध) विक्रम सिंह ने बताया, कई महीनों की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद अपराध शाखा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक माओवादी चरमपंथी की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी। इस सूचना पर पुलिस की टीम ने चार मार्च को महाराणा प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा में छापेमारी की और इस दौरान महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि किसान परिवार में उसका जन्म हुआ था और वह 10 वर्ष की आयु में ही माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुट में शामिल हो गई थी। पुलिस उपयुक्त ने बताया, महिला नक्सली ने झारखंड के कोल्हान जंगल में रमेश नामक कमांडर के नेतृत्व में पांच साल तक गहन प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान उसे इंसान राइफल, एसएलआर, एलएएमजी, हथगोला और 0.303 राइफल जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना सिखाया गया। (शेष पृष्ठ 9)

तीन साल में प्रदूषण मुक्त होगी यमुना : प्रवेश वर्मा

●बोले, 10 दिन में हटाया 1300 टन कचरा, दिल्ली में इस साल नहीं आएगी बाढ़

संजय राय। नई दिल्ली



विधानसभा चुनाव में यमुना को प्रदूषण मुक्त करन का मुद्दा गरमा था। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने का बाद यमुना नदी की साफ-सफाई का काम जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा बुधवार को नदी कंके सफाई अभियान का बोट क्लब से सिन्नेचर ब्रिज और आईटीओ छठ घाट तक निरीक्षण किया और दावा किया कि पिछले 10 दिनों में नदी से 1300 टन कचरा निकाला गया। वर्मा ने कहा कि वर्ष 2023 में दिल्ली को बाढ़ का सामना करना पड़ा था। जिसकी मुख्य वजह फ्लोटिंग्स का बंद पड़ा रहना था लेकिन, अब अगले से बाढ़ का कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि फ्लोटिंग्स की मरम्मत कर दी गई और साथ-साथ इसे ऊंचा कर दिया गया। दिल्ली सरकार यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसे लेकर ऐक्शन प्लान बनाया है जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। वर्मा ने दावा किया कि आने वाले तीन साल में यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। इस कार्य में दिल्ली

सरकार के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय भी सक्रिय है। प्रवेश वर्मा यमुना नदी का निरीक्षण करने के बाद सफाई कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कहा, दिल्ली के सभी नालों को सड़ाने बन्दाने का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि नदी तटों की सफाई और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यमुना रिवरफ्रंट विकसित करने का निर्देश दिया है, जिससे नदी तट एक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले दशक में नदी की सफाई के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया, यहां तक कि कागजों पर भी कुछ नहीं किया गया। पिछली सरकार को यमुना के लिए काम करने का ख्याल भी नहीं आया। लेकिन अब, न केवल दिल्ली सरकार बल्कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसमें शामिल है। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा

करते हुए वर्मा ने कहा कि रसायनिक अपशिष्टों का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, बाढ़ को रोकने के लिए आईटीओ बैराज द्वारा पर सुरक्षा दीवारों की मरम्मत और ऊंचाई बढ़ाने का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि नदी तटों की सफाई और हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हमने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यमुना रिवरफ्रंट विकसित करने का निर्देश दिया है, जिससे नदी तट एक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले दशक में नदी की सफाई के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया, यहां तक कि कागजों पर भी कुछ नहीं किया गया। पिछली सरकार को यमुना के लिए काम करने का ख्याल भी नहीं आया। लेकिन अब, न केवल दिल्ली सरकार बल्कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसमें शामिल है।

वर्मा ने कहा कि उनकी सभी लोगों से अपेक्षा और प्रार्थना है। हम बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी से भी सहयोग ले रहे हैं। मशीन काम कर रही हैं। पिछले 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं है। कोई काम कागज पर भी नहीं हुआ। पिछली सरकार के दिमाग में यमुना नदी को साफ करने की बात भी नहीं है। सरकार का लक्ष्य 3 साल में यमुना साफ हो करने का है। पानी का रंग काला है। 3 साल में इस रंग को बदलकर दिखा देंगे।

सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी: मंत्री प्रवेश वर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार संकल्प है। यमुना में जो 18 नाले गिरते हैं, वहां सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां भी नए सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 2 साल का समय इस कार्य में लगेगा। यमुना की सफाई का काम भी घाट पर दिखाई दे रहा है। यहां पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। सभी लैंडमार्क की पहचान कर ली गई है। इस काम में किसी भी कीमत पर कोई डिलेयड बर्दास्त नहीं की जाएगी। दिल्ली वालों से अनुरोध किया कि वे नदी में कचरा न फेंके और इस मुहिम में अपना सहयोग दें।

रेलवे ने आंतरिक पदोन्नति प्रणाली में सुधार पर दिया जोर

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

भारतीय रेलवे नेटवर्क में नौकरियों, पदोन्नति से संबंधित मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जाल में कई रेल अधिकारियों के फंसने के बाद, रेलवे बोर्ड ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया कि 13 लाख रेल कर्मचारियों के लिए सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) योग्यता के माध्यम से केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से ली जाएंगी। रेलवे के सूत्रों ने कहा कि सभी जौनल रेलवे को परीक्षा के लिए एक कैलेंडर तैयार करना होगा और सभी परीक्षाएं

कैलेंडर के आधार पर ही आयोजित की जाएंगी। सूत्रों ने कहा, आरआरबी द्वारा हाल के वर्षों में आयोजित पारदर्शी, निष्पक्ष और अत्यधिक प्रशंसनीय परीक्षाओं के लंबे अनुभव के बाद यह निर्णय लिया गया है। एक दिन पहले सीबीआई ने एक बड़े अभियान में पूर्व मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सहित 26 रेलवे अधिकारियों को एक विभागीय परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और छापेमारी के दौरान 1.17 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। एजेंसी ने बताया कि मुगल सराय में मुख्य लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति के लिए परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के

आरोप में रेलवे अधिकारियों को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि परीक्षा मंगलवार को होनी थी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह गिरफ्तारी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा वडोदरा डिवीजन में तैनात भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) के दो अधिकारियों सहित पांच रेलवे अधिकारियों को विभागीय परीक्षा में उम्मीदवारों के पक्ष में कथित रिश्तखोरी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक पखवाड़े बाद हुई। अभी तक, आंतरिक रिक्तियों की पदोन्नति तय होती थी, जिसमें शीर्ष अधिकारियों से लेकर अन्य हितधारकों तक की बड़ी सांठगांठ थी। जिससे यह हितधारकों



के लिए एक बड़ा रैकेट और गठबंधन बन गया था। यह निर्णय दिन की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें

समीक्षा की गई कि आरआरबी बिना किसी शिकायत के, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, 2015 से लेकर आज तक सात करोड़ से अधिक उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के माध्यम से बिना किसी पेपर लीक, प्रतिरूपण, रिमोट लॉग-इन और जासूसी उपकरणों के उपयोग के परीक्षा ली गई है। इस प्रक्रिया में खुली निविदा के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी का चयन करना शामिल है, जिसमें सभी उपलब्ध सुविधाओं के लिए सख्त ऑफ़डेटिंग चेकलिस्ट बनानी होगी, जैसे कि बाहर शौचालय की अनुमति नहीं है, 100 प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज और रिकॉर्डिंग परीक्षा से दो

घंटे पहले और परीक्षा के एक घंटे बाद की जानी चाहिए। एसओपी में बेहतर रिजल्टयूशन, विश्वसनीय और निबंध कनेक्शन के लिए आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी, वार्शियनिक और अन्य आवासीय क्षेत्र से अलगाव शामिल है। ऑफ़डेटेड श्रेय के लिए सभी माउस और कुंजी क्लिक को टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। परीक्षा की वास्तविक तिथि से 10 दिन पहले परीक्षा के शहर के बाहर में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए, जबकि परीक्षा का स्थान/केंद्र परीक्षा से केवल चार दिन पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र को मैन्युअल

हस्तक्षेप से बचने के लिए कम्प्यूटीकृत और यादृच्छिक (रैंडमाइजेशन) के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। परीक्षा आयोजित करने वाली टीम और परीक्षा केंद्र के कर्मियों को परीक्षा से दो घंटे पहले उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रश्न-पत्र अत्यधिक एन्क्रिप्टेड स्वरूप (256-बिट एन्क्रिप्शन) में होना चाहिए तथा अंतिम क्षण में डिजिटल केवल तभी होगा जब अभ्यर्थी वास्तव में लॉग-इन करेगा। अंततः निगरानी की कई चरणों में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी ताकि इसे डिस्टर्बित बनाया जा सके।

अबू आजमी को पार्टी से निकाले और यूपी भेजे सपा, यहां उसका 'उपचार' किया जाएगा: योगी

● महुंके मुख्मन्त्री, कल- लोहिया के रास्ते से म्कटी सपा औरंगजेब को बना रही आदरती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को 'महान प्रशासक' बताया हुए उसकी प्रशंसा की थी। इस बयान के बाद यूपी विधान परिषद में मुख्मन्त्री ने सपा को आड़े हाथ लिया है। मुख्मन्त्री ने सदन में कहा कि सपा भारत की संस्कृतिक विरासत पर गर्व नहीं करती और अपने मूल विचारक डॉ. राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि डॉ.

लोहिया ने भारत की एकता के तीन आधार बताए थे- श्रीराम, श्रीकृष्ण और भगवान शिव, लेकिन आज सपा औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श मान रही है। योगी ने औरंगजेब के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसाया था।

उन्होंने सपा नेताओं को पटना की लाइब्रेरी में शाहजहां की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि शाहजहां ने औरंगजेब को कहा था कि तुम से अच्छा तो हिन्दू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां-बाप की सेवा करता है और मृत्युपरत वर्ष में एक बार श्राद्ध करते हुए मां-बाप को जल अर्पित करता है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों का आचरण औरंगजेब

जैसा है वो उसपर गर्व कर सकते हैं। योगी ने सपा पर भारत की आस्था पर प्रहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और भारत का इस्लामीकरण करने की कोशिश की। कोई सभ्य मुसलमान अपने बेटे का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि वह उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा। उन्होंने सपा से सवाल किया कि वह महाकुम्भ जैसे आयोजन को आलोचना करती है और दूसरी ओर औरंगजेब जैसे 'दुदांत और धर्मांध' शासक का महिमामंडन करती है। मुख्मन्त्री ने सपा को चुनौती दी कि वह अपने विधायक (अबू आजमी) को पार्टी से निकाले और उसे यूपी भेजे, यहां उसका 'उपचार' किया जाएगा।

विधायकों को अब दिए जाएंगे सिर्फ दो वाहन पास

● अलग से पास के लिए सचिवालय प्रशासन अधिकृत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को निमित होने वाले प्रवेश पत्रों के दुरुपयोग होने का उल्लेख करते हुए नई व्यवस्था दी। उन्होंने इस बात के एक घटना का उल्लेख करते हुए कि पिछले दिनों फिट एंड रन के मामले में पुलिस को एक वाहन पर विधायक का फर्जी आईडी पास लगा मिला था। इसके अलावा विधानसभा परिसर में भी एक वाहन पर फर्जी पास इस्तेमाल की सूचना पुलिस द्वारा दी गई है। विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है। सुरक्षा के जुड़े हुए इस प्रकरण में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि नई व्यवस्था के तहत नए पास जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि अब अप्रैल से आरएफआईडी प्रवेश पत्र विधायकों को दिए जाएंगे। उन्हें सिर्फ दो वाहन पास मुहैया कराए जाएंगे। विधायक अपने कार्यकर्ताओं सार्थकों के लिए वाहन पास के लिए सचिवालय प्रशासन से संपर्क करें। विधायकों को भी अलग से पास देने के लिए सचिवालय प्रशासन अधिकृत है। सचिवालय प्रशासन द्वारा पास अलग से जारी किए जा सकेंगे। इसी के साथ उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि विधायकों के डिजिटल पास बन चुके हैं और पदल पर उपलब्ध हैं, वे प्राप्त कर लें और विधानसभा की सुरक्षा बनाए रखने में विधानसभा सचिवालय प्रशासन का

सहयोग करें। उन्होंने विधायकों को आश्चर्य किया कि वे प्रयास करेंगे कि संसद की तर्ज पर विधायकों को वाहन प्रवेशपत्र निर्गत किए जाएं। आज ही सपा के सदस्य कमाल अख्तर तथा इंजीनियर सचिन यादव ने एकसत्रेसवे पर टोल प्लाजा पर विधायकों का अपमान करने का मामला उठाया। कमाल अख्तर ने कहा कि टोल पर कर्मचारियों के चरित्र की जांच करवा ली जाए। उनसे अपराधिक चरित्र के बारे में देखा जाए। उन्होंने कहा कि टोल कर्मचारियों का विधायकों के प्रतिव्यवहार काफी अपमान जनक होता है। सपा के ही इंजीनियर सचिन यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारी और आईएस तो अपने परिवारियों के लिए भी पास अलग से बनवाते हैं। अधिकारियों को टोल वाले खुलेआम जाने देते हैं। उन्हें कोई रोक-टोक नहीं है। अगर विधायक के पास गनर न हो तो और भी दिक्कतें हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियम हैं लेकिन यह ध्यान रखें कि पास विधायकों के लिए हैं कर्मचारी रिश्तेदारों के लिए नहीं। यह व्यवस्था हर सरकार में रही है। आज का एक सदस्य विपिन वर्मा ने आज अधिकारियों के कक्ष में विधायकों का प्रवेश आमनागिरकों की तरह कराए जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब किसी अधिकारी के यहां कोई दूसरा अधिकारी जाता है तो उसके प्रवेश के लिए मुख्मन्त्री खोला जाता है जबकि जनप्रतिनिधियों को आम नागरिकों की तरह स्टाफकक्ष से प्रवेश दिया

विधानसभा परिसर में पान मसाला, गुटखा पर लगा प्रतिबंध

विधानमंडल का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

लखनऊ। बजट सत्र के अंतिम दिन सतीश महाना ने विधानसभा परिसर में पान, पान मसाला या गुटखा खाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की साथ ही विधायकों को निमित होने वाले वाहन प्रवेशपत्रों में नई नियमों की सूचना दी। उन्होंने अपनी व्यवस्था देते हुए कहा कि अब यदि कोई विधानसभा में पान, पान मसाला या गुटखा खाते हुए पाया जाता है। तो उससे पांच सौ

रूपए का जुर्माना लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष की यह व्यवस्था आज तब आई जब बुधवार को किसी सदस्य ने दुदांत के परिसर में पान की पीक थूक दी थी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस सदस्य को चिन्हित भी कर लिया था लेकिन उन्होंने उस सदस्य का नाम सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने इस बारे में सदस्यों को चेतावनी देते हुए ऐसा दुबारा न करने की चेतावनी दी।

जाता है। इस पर विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना को निर्देश दिया वे मुख्मन्त्री से बात करके यह सुनिश्चित कराए कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की तरह सम्मान के साथ प्रवेश दिया जाए। सपा के सदस्य अतुल प्रधान ने बड़ौते में जैन समाज के एक धार्मिक आयोजन में हुई भावदंड के मामलों में नौ लोगों के मारे जाने का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा न तो मृतकों को श्रद्धांजलि दी गयी न ही उनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी गयी। उन्होंने कहा जिस तरह कुंभ में मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया उसी तरह बागपत के धार्मिक आयोजन में मारे गए लोगों को भी पचास-पचास लाख का मुआवजा दिया

जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्मन्त्री एक आयोजन में बागपत गये थी थे लेकिन उन्होंने वहां जाकर मृतकों के परिजनों के लिए कोई घोषणा नहीं की। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि संबंधित घटना के सिलसिले में एचोएम की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गयी है। जहां तक मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का प्रश्न है तो मुख्मन्त्री के विवेक पर निर्भर है। इस बारे में उनसे बात करके कोई निर्णय लिया जा सकेगा। संसदीय कार्यमंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सदस्य अतुल प्रधान से सदन से वाकआउट किया। आज ही सपा के फहीम इफ्तान कोराना काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में मारे गए लोगों को भी पचास-पचास लाख का मुआवजा दिया

सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से असफल: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



कहा कि किसानों को फसलों के लिए पहले खाद-बीज और कीटनाशक नहीं मिलता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उन्हें फसलों की सही कीमत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यर्थाने व्यर्थाने कोषपूर्ण जीएसटी से परेशान है। व्यापारियों पर छापे डलवाकर भाजपा सरकार उन्हें प्रताड़ित करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। हत्याए लूट और बलात्कार की घटनाए बढ़ती जा रही है।

कहा कि किसानों को फसलों के लिए पहले खाद-बीज और कीटनाशक नहीं मिलता, जब फसल तैयार हो जाती है तो उन्हें फसलों की सही कीमत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यर्थाने व्यर्थाने कोषपूर्ण जीएसटी से परेशान है। व्यापारियों पर छापे डलवाकर भाजपा सरकार उन्हें प्रताड़ित करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। हत्याए लूट और बलात्कार की घटनाए बढ़ती जा रही है।

प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ती जा रही है बर्बरता: तनुज पुनिया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चैयरमैन, सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं वो तो न सिर्फ बढ़तूर जारी हैं, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। जैसे किसी दलित की बारात न उठने देना, दूल्हे का घोड़े चढ़ने पर एतराज, मूँछ रखने न देना मगर आंकट्ट दलितों के खिलाफ नफरत में डूबी सरकार में इस तरह के अपराध आए दिन होने लगे हैं। तनुज पुनिया बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश में लगातार दलितों

को खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और अपराध की घटनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मेरठ के कालिंदी गांव में 1 मार्च 2025 को गांव को ठाकुर बिरादरी के दबंगों द्वारा दलित की बारात पर हमला किया गया। दूल्हे के भाई संदीप को पीटा गया, दूल्हे को अपमानित कर सोने की अंगुठी, ब्रेसलेट और केश लूट लिया गया। दबंग भाजपा की झंडा लगी हुई गाड़ी से आए थे जो बरातियों में से कई

यूनिक इवेंट बनकर दुनिया को लंबे समय तक अपनी ओर आकर्षित करेगा महाकुम्भ: योगी

● विधानसभा में बोले मुख्मन्त्री संवाद व विचारों की अभिव्यक्ति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



महाकुम्भ ने बदली यूपी की अर्थव्यवस्था

योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में महाकुम्भ के आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विरासत को विकास से जोड़ने' के मंत्र की सराहना की और बताया कि काशी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे तीर्थस्थलों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सीएम योगी ने कहा कि 2019 से पहले काशी में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित थी, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद काशी ने नया रूप लिया। 13 जनवरी से 27-28 फरवरी तक काशी पूरी तरह पैक रही। रोजाना 5 से 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे, मां गंगा में स्नान किया और काशी के वैभव से अभिभूत हुए। उन्होंने काशीवासियों के आतिथ्य सत्कार और धैर्य की भी सराह। अयोध्या में भी यही स्थिति रही, जहां प्रतिदिन 5 से 15 लाख श्रद्धालु पहुंचे। योगी ने कहा कि अयोध्या के नागरिकों और संतों ने अपनी सुविधाओं की परवाह न करते हुए श्रद्धालुओं का स्वागत किया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 28-29 जनवरी को 2 लाख वाहनों को आसपास के जनपदों में रोका गया, जहां स्थानीय लोगों ने भोजन और पानी की व्यवस्था की।

सपा सरकार ने गंगा की शुद्धता के लिए नहीं उठाया कोई कदम

मुख्मन्त्री ने कहा कि गंगा की अवरिचलता व पवित्रता के बारे में प्रश्न उठ रहा था। मां गंगा बिजनेस से बलिया तक 1000 किमी. दूरी तय करती हैं। नमामि गंगे परियोजना (2014) के पहले सबसे क्रिटिकल प्वाइंट कानपुर था। यह न सिर्फ यूपी, बल्कि गंगोत्री से लेकर गंगासागर के 2500 किमी. के दायरे में था। कानपुर में 125 वर्ष से सीमांकन में चार करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई। यद्यपि पैसा 2015 में ही उपलब्ध कराया गया, लेकिन सपा की तत्कालीन सरकार ने उसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रदूषण को बात करने वाले वही लोग हैं, जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए।

हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा

मुख्मन्त्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्मन्त्री ने अपने संबोधन में विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सशक्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में उत्सव भवन का निर्माण किया जाएगा।

किसानों के हित में उठाए गए बड़े कदम

सीएम योगी ने कहा कि यूपी खाद्यान्न उत्पादन में नंबर एक है और कृषि विकास दर 14ब तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28.58 लाख किसानों ने बीमा कराया, जिसमें 9.33 लाख को 495.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिली। साथ ही, 2.73 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान और 119 चीनी मिलों की बढ़ी क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यूपी 400 लाख टन सब्जियों के उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादकता 27.25 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 30.51 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। तिलहन उत्पादन में 128 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। धान और गेहूं खरीद में भी तीन से पांच गुना तक का इजाफा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार अन्नदाता किसानों के लिए माता शवरी के नाम पर मंडियों में कैटेनि और विश्रामालय स्थापित करने जा रही है।

प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनेगा छात्रावास

मुख्मन्त्री योगी ने विपक्ष को संविधान के सम्मान और संरक्षण को लेकर जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये दल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य दलित-पिछड़े महापुरुषों को की सम्मान नहीं दे पाए। जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और पंच तीर्थों के निर्माण जैसी कई ऐतिहासिक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए बनने वाले सभी छात्रावासों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यह वर्ष भारत के संविधान अंगीकार करने का अमृत महोत्सव वर्ष है।

मंत्री राकेश सचान ने होली पर्व पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी तथा ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बुधवार को खादी भवन डालीबाग लखनऊ में ष्चोली के शुभ अवसर पर 5 दिवसीय लघु खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनीए का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्य द्वार पर फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार

लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 मंडलों में खादी एवं ग्रामोद्योगी प्रदर्शनीयों का आयोजन किया गया है, जिसमें 2372 स्टाल लगे और 4423.67 लाख रुपये की बिक्री हुई। प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित खादी स्टालों पर 13.84 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में पहली बार बोर्ड परिसर में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मंत्री ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, जो स्वदेशी, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने

यह भी बताया कि खादी उत्पादों का निर्माण अब फिट जैसी वैश्विक संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग विभाग स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि इंद्रौर गांधी प्रतिष्ठानए लखनऊ में आयोजित 'खादी महोत्सव 2025' में 133 इकाइयों ने भाग लिया और 2.54 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की। उन्होंने उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रदेश में खादी से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और सरकार इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएँ तलाश रही है। मुख्मन्त्री का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद स्थानीय कलाकारों ने होली गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।

परिसर में चलेगीए जहां आगंतुक खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। 35 स्टालों पर स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में लखनऊ मंडल के विभिन्न जनपदों के उद्यमियों द्वारा अपने उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसमें हर्बल गुनाल, पापडूए, बरी, नमकीन, शहद, आंवला उत्पाद, खादी बोर्ड जनसामान्य तक योजनाओं को पहुंचाने और न्यूनतम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए कार्यरत है। प्रदर्शनी का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ, जिसके बाद स्थानीय कलाकारों ने होली गीतों की शानदार प्रस्तुति दी।

जनहित में मार्च के अंतिम रविवार को भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय: रवींद्र जायसवाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल द्वारा आम जनमानस को विलेख पंजीकरण का अधिकाधिक अवसर व सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया है कि प्रदेश के समस्त उप.निबन्धक कार्यालय माह मार्च 2025 के अंतिम रविवार को सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे तथा विलेख पंजीकरण का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किया जायेगा, ताकि उक्त अवकाश के दिन भी आम जनमानस के द्वारा विलेखों का अधिक संख्या में पंजीकरण कराया जा सके और विभाग को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति

सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय समापन एवं माह मार्च में होली व नवरात्रि के त्योहार के कारण इस माह में आम जनमानस द्वारा अधिक संख्या में अचल सम्पत्तियों का पंजीकरण कराया जाना सम्भावित है। माह मार्च में होली आदि त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश के कारण माह में उपलब्ध कार्य दिवस अपर्याप्त होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही माह मार्च 2025 के अन्य अवकाश दिवस अथवा रविवार को उप.निबन्धक कार्यालयों को निबन्धन कार्य हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

आवंटित बजट का एक भी पैसा लैप्स नहीं होना चाहिए: जयवीर



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्वटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व सभी मंडों में आवंटित धनराशि का शत.प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में बजट का सरेन्द्र न किया जाए। इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करें। कार्य समाप्ति हो जाने के बाद संबंधित योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

संस्कृति मंत्री बुधवार को पर्यटन भवन में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की वित्तीय प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष अधिघातन भेजने की कार्यवाही तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये, इसके साथ ही पदोन्नति के मामलों में किसी स्तर पर विलम्ब न किये जाने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि पदरिक्त होने से विभागीय योजनायें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य ललित कला अकादमी द्वारा मूर्ति निर्माण का कार्य भी समय से पूरा करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त स्थापित मूर्तियों का भूतल खनिकर्म से धातु के मिश्रण की जांच

अनुसंधान कार्यों को मजबूत करें विश्वविद्यालय: राज्यपाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में 'रैंकिंग उन्नयन-2025' कार्यशाला का हुआ आयोजन



देशी होगी ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। उन्होंने इस दिशा में सभी विश्वविद्यालयों को संगठित प्रयास करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से मिले विचारों और सुझावों को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उन पर गंभीरता से चिंतन करें और जब यहां से वापस जाएं तो टीमवर्क की भावना से कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश कि वे कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को आपस में साझा करें और उन पर गहन

चर्चा करें, जिससे नए विचार सामने आएँ और योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि कार्यशालाएं और सेमिनार तभी सफल माने जाते हैं जब उनमें दी गई जानकारी से प्रतिभागियों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जब चार लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और एक-दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करते हुए कार्य करते हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे युवा प्रतिभागियों को अवसर दें क्योंकि नवाचार और ऊर्जा

से भरे युवा ही संस्थानों को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपनी सोच बदलनी होगी और परस्पर सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि संस्थानों को केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने के बजाय आपसी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान पर जोर देना चाहिए, ताकि सभी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने विश्वविद्यालयों की वेबसाइटों की गुणवत्ता पर भी ध्यान

देने की आवश्यकता बताई और कहा कि वेबसाइट्स पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे छात्रों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रावास, अनुसंधान सुविधाएं, पाठ्येतर गतिविधियां और अन्य सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर स्पष्ट और आकर्षक रूप में उपलब्ध हो। राज्यपाल ने अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने अनुसंधान कार्यों को मजबूत करना होगा और उन्हें प्रासंगिक तथा प्रभावशाली बनाना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वविद्यालयों को मिलकर अनुसंधान करना चाहिए, पीएचडी के कार्यों में सहयोग बढ़ाना चाहिए, पुस्तक लेखन और अनुवाद कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ज्ञान का व्यापक प्रसार हो सके।

90 दिनों के बाद पकड़ा गया बाघ इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस

● बेंगलुरु से आई टीम ने ट्रैकुलाइज कर किया बेहोश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



काकोरी इलाके में पिछले 90 दिनों से चली आ रही दहशत बुधवार को बाघ के पकड़े जाने के बाद खत्म हो गयी। वन विभाग की टीम ने जोन-2 में मीठेनगर के पास बाघ को पहले ट्रैकुलाइज कर बेहोश किया, फिर उसको पकड़ा। इस दौरान मौके पर वन विभाग के 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व डॉक्टर भी उपस्थित थे। वन विभाग की टीम का कहना है कि आगे भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ाई जाएगी।

बाघ अब तक 20 से अधिक पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। पकड़े जाने से पहले बुधवार की सुबह भी गेहूँ के खेत में एक गाय को मार डाला। इसके पहले

सोमवार को भी एक पड़वा (बछड़ा) का शिकार किया था। बाघ को पकड़ने के लिए विभाग ने अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया। बेंगलुरु से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए गए जो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरों के जरिए बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। ये कैमरे खास तकनीक से लैस थे, जो बाघ की पहचान होते ही महज 1 मिनट के भीतर उसकी लोकेशन वन विभाग की ईमेल पर भेज देते थे। वन विभाग के ड.नासिर, डॉ. दक्ष और डॉ. आरके सिंह टीम के साथ बुधवार को सुबह पांच बजे से ही बाघ के होने की चलते निगरानी करने में जुट गए थे। शाम को करीब 6.09 बजे रहमानखेड़ा के पास उस पर बेहोशी के लिए पहला वार किया गया।

शराब की दुकानों के आवंटन का मामला लाटरियां खुलेंगी, व्यवस्थापन पर आज तक के लिए रोक



विधि संवाददाता। लखनऊ

का कहना है कि उक्त शासनादेश सम्बंधित नियमावली के नियम 5 के विरुद्ध है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश वकील एलपी मिश्रा का कहना था कि इसी विषय पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में एकल पीठ के समक्ष विचारार्थीन है। लिहाजा यह याचिका भी एकल पीठ द्वारा ही सुनी जानी चाहिए। पीठ ने इस पर हाईकोर्ट के सम्बंधित अनुभाग को निर्देश दिया कि वर्तमान याचिका के सम्बंध में वह अपनी रिपोर्ट दें कि यह एकल पीठ द्वारा सुने जाने योग्य है अथवा नहीं।

बचे हुए स्टॉक की कीमत वापस करें: वहीं इसी मसले पर दाखिल दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष भी हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ ने दुकानों के पुनर्आवंटन में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। लेकिन सरकार को आदेश दिया है कि वर्तमान आवंटियों के दुकानों पर बचे हुए स्टॉक का उपयुक्त मूल्य वापस किया जाए। एकल पीठ का कहना था कि शराब की दुकान का लहनासे कोई संचिधानिक अधिकार नहीं है। लिहाजा यह अदालत सरकार के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

शराब की दुकानों के आवंटन के सम्बंध में गुरुवार को होने जा रही लाटरी प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम आदेश पारित किया है। पीठ ने कहा है कि शराब की दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बंध में यदि लाटरी खुलती है, तो भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पीठ ने यह रोक फिलहाल सिर्फ गुरुवार तक के लिए लगाई है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

जस्टिस राजन राय एवं जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की पीठ ने यह आदेश सीतापुर के रामचंद्र व अन्य की याचिका पर दिया है। इन याचिकाओं में बीते छह फरवरी के उस शासनादेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत शराब की दुकानों का पुनर्आवंटन लाटरी प्रक्रिया से करने की बात कही गई है। याचिकाकर्ताओं

उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहद संभावनाशील: मनोज सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) द्वारा होटल ताज में आयोजित वार्षिक सत्र-2025 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। वार्षिक सत्र में 'प्रदेश की परिवर्तनकारी सफलता: उत्तर प्रदेश भारत के विकास के इंजन के रूप में उभरती अर्थ व्यवस्था' विषयक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आया है, जिससे यह रोजेय सरप्लस राज्य के रूप में उभरा है और प्रदेश में एक सशक्त औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। इस प्रगति ने वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की छवि को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने

कहा कि विधानसभा में लगभग 8 लाख 8 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जो देश का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। इन सब के पीछे इंडस्ट्रीज का अहम योगदान है। आज प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के अपूर्व सफल आयोजन ने यह प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर वैश्विक आयोजनों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ आयोजन किया गया। उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, जे.के. सीमेंट लिमिटेड माधव

सिंघानिया ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पान क्षमता बेजोड़ रही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश तेजी से वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है और राज्य की आर्थिक रूपांतरण यात्रा को बल मिल रहा है। सीआईआई उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष एवं निदेशक व सीएफओ, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्मिता अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत के सबसे गतिशील आर्थिक केंद्रों में से एक बन चुका है। सीआईआई उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल डॉ. उपासना अरोड़ा ने कहा

मुख्य सचिव ने कार्यशाला का उद्घाटन कर महिला ग्राम प्रधानों से किया सीधा संवाद

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025) के उपलक्ष्य में महिला प्रधानों के लिए 'ऊर्जा, विकास की बात: महिला प्रधान के साथ' विषयक आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महिला प्रधानों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला प्रधानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहल को लागू कर रही है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन और महिला अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने महिला प्रधानों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा संरचना में तेजी से प्रगति हो रही है।

यूके का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा एकेटीयू निवेश और व्यापार पर हुई चर्चा



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में बुधवार को यूनाईटेड किंगडम यूके का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस दौरान इन्वेंशन हब की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिनिधिमंडल के अलावा स्टार्टअप और इन्वेंयुवेंटर्स शामिल हुए। बैठक में यूके के प्रतिनिधिमंडल ने यूके और यूपी में व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा की। बताया उत्तर प्रदेश में यूके और यूपी दोनों जगहों पर स्टार्टअप और इन्वेंयुवेंटर्स के लिए पर्याप्त अवसर हैं। साथ ही आपसी सहयोग पर भी चर्चा की गयी। यूपी के

स्टार्टअप को सहयोग देने पर विचार किया। इसके अलावा स्टार्टअप में निवेश को लेकर भी मंथन किया गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने अपने दौर और अपने स्टार्टअप के बारे में विस्तार से बताया। एक दूसरे से सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम के आदान-प्रदान पर भी सहमति बनी। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत डीन इन्वेंशन प्रो. बीएन मिश्रा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी में अवसर और संसंधान की कोई कमी नहीं है। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप और इन्वेंशन के लिए मुफुदी है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से सहयोग की अपील की।

इग्नू का अड़तीसवाँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अड़तीसवाँ दीक्षान्त समारोह बुधवार को सम्पन्न हुआ। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय में मंगलागढ़ी, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहाँ धर्मेन्द्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, मुख्य अतिथि एवं प्रो पवन कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, तिरुचिरापल्ली, विशिष्ट अतिथि रहे। इसी तारतम्य में 39 क्षेत्रीय केन्द्रों पर समानान्तर दीक्षान्त समारोह आयोजित किया गया, जहाँ पर पराष्वातक एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपाधि प्रदान की गयी।

लखनऊ में यह कार्यक्रम इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के सभागार में आयोजित किया गया। इस बार क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ के 5 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गयी। लखनऊ में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। जिसमें अनिमेष बरुआ को राजनीति विज्ञान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं डिग्री

प्रदान की। वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ अनिल कुमार मिश्र ने क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ की प्रगति आख्या में कहा कि इग्नू अपनी विशेषताओं के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और हाल में ही इसे एनआईआरएफ रैंकिंग में दूरस्थ विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि इग्नू की स्थापना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के द्वार तक ले जाकर उन्नत, धर्म, क्षेत्र और लिंग बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ कराना है।

250 से अधिक लोगों ने जांच कराकर चिकित्सीय परामर्श लिया



लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॅरिसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस), लखनऊ में 4 मार्च 2025 से दो दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें दो दिनों में लगभग ढाई सौ से अधिक लोगों ने अपने जांच एवं चिकित्सीय परामर्श लिए। चिकित्सा शिविर के समापन के अवसर पर संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने चिकित्सा शिविर में मैक्स सुपर स्पेशलिटी नई दिल्ली के प्रमुख हृदय रोग चिकित्सक डॉ. विवेका कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने शिविर में लोगों को कुशलता पूर्वक देखने एवं परामर्श देने के लिए डॉ. अतुल कुमार एवं डॉ. अतिवृद्धा खान का भी संस्थान के तरफ से आभार व्यक्त किया।

मोहनलालगंज में भूमिहीन परिवारों के लिए ख्वाब बन गया सपनों का घर

संवाददाता। मोहनलालगंज

आवासीय पट्टे नहीं मिलने से मोहनलालगंज में भूमिहीन परिवारों के अपने घर का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे कई लाभार्थियों को आवासीय पट्टे देने के लिए ब्लॉक और तहसील के बीच कई बार पत्र व्यवहार भी हो चुके हैं। फिर भी गरीबों को आवास बनाने के लिए अब तक पट्टे नहीं दिए जा सके हैं। कर्मोवेश यही हाल नगर पंचायतों का भी है। मोहनलालगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिसेंडी निवासी मोहम्मद रफीक को वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास दिया गया था। भूमिहीन होने से रफीक के परिवार को आवासीय पट्टा देने के लिए ग्राम पंचायत और ब्लॉक की ओर तहसील को पत्र भेजा गया। लेकिन चार वर्ष बाद भी रफीक के परिवार को न तो आवासीय पट्टा मिल सका और न ही

● आवासीय पट्टे नहीं मिल पाने से गरीबों के प्रधानमंत्री आवास के निर्माण लटके

उनके सपनों का घर बन सका। लिहाजा आशियाने के इंजिनर में ही रफीक का देहांत हो गया। इसी तरह इलाकों की बुजुर्ग निर्मला के मामले में भी तहसील प्रशासन आवास निर्माण के लिए आवासीय पट्टे नहीं दे सका है। मीरानपुर में भी एक लाभार्थी का आवास पट्टे के अभाव में अटका पड़ा है। कनकहा और नगराम इलाके में आवासीय पट्टा नहीं मिल पाने से दो लाभार्थियों ने सरकारी

जमीन पर आवास का निर्माण करा लिया था। जिसे शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने अतिक्रमण खाली करा दिया। लिहाजा आवास योजना का लाभ मिलने के बाद भी इन जरूरतमंद परिवार के सपनों के घर का ख्वाब अधूरा ही रह गया। यही नहीं नगर पंचायत में रहने वाले एक गरीब परिवार को भी आवास निर्माण के लिए तहसील अधिकारी आवासीय पट्टा नहीं दे सके। लिहाजा बेबस परिवार ने जोखिम लेकर सरकारी भूमि पर निर्माण करा लिया। नगर पंचायत में भी अभी कुछ ऐसे भूमिहीन परिवार हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा है। लेकिन आवासीय पट्टे के अभाव में उनके सपनों के घर का ख्वाब हकीकत में नहीं बदल सकेगा। बीडीओ आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे परिवारों को आवासीय पट्टे देने के लिए तहसील को पत्र भेजा जा चुका है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए नागरिक घोषणा-पत्र जारी



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नागरिक घोषणा-पत्र का विमोचन उग्र सचिवालय स्थित तिलक हाल में किया। इस घोषणा-पत्र के तहत शिक्षकों, शिक्षणेत्र कर्मचारियों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा तय की गई है, जिससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह नागरिक घोषणा-पत्र माध्यमिक शिक्षा में अनुशासित कार्य-संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं

● राजकीय व अशासकीय शिक्षकों के सेवा प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा

को विहित कर उनकी समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा-सम्बंधी मामलों जैसे अवकाश, पेंशन, प्रोन्नति, वेतनमान, जीपीएफ और मृतक आश्रित नियुक्तियों के निस्तारण के लिए भी स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार इस घोषणा-पत्र से त्वरित, पारदर्शी, सुगम, जवाबदेही और जन-हितैषी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में महिला सुरक्षा पर रहेगा जोर: रेखा

● संवाद में आर्थिक सहायता, महिला की भागीदारी, बेहतर शिक्षा समेत कई मुद्दों को उठाया गया

● सीएम के तीन दिवसीय कार्यक्रम में झुगगी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों से मुलाकात और युवाओं से भी बातचीत करेंगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विकसित दिल्ली बजट पर विधान सभा में आयोजित विभिन्न महिला संगठनों के साथ संवाद कर विस्तार से चर्चा की। इस संवाद में महिलाओं ने बहू-चहकर भाग लिया और बजट से संबंधित विभिन्न मुद्दों और महिलाओं से संबंधित सुझाव साझा किए।

विकसित दिल्ली बजट पर महिला संवाद में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, आर्थिक सहायता, महिला की भागीदारी बढ़ाना, बेहतर शिक्षा, सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और शौचालय की व्यवस्था आदि विषय महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से उठाया गया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों ने सभी विषयों पर खुलकर बात की और उनके साथ मिलकर हम विकसित दिल्ली बजट को नया आकार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार जो कार्य पहले नहीं कर पाई, वह अब जरूर पूरे होंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं और अन्य



फोटो: रंजन डिमरी

विकसित दिल्ली बजट पर विधान सभा में आयोजित विभिन्न महिला संगठनों के साथ संवाद करती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

सचिवालय में शिक्षाविदों के साथ किया विमर्श

● कहा, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार उठाएगी सभी कदम

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विकसित दिल्ली बजट को लेकर सचिवालय में शिक्षाविदों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो देश में सर्वोत्तम हो। इस दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। इस संवाद में शिक्षा से जुड़े विषयों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों ने अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही चुनौतियों पर खुलकर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए।

दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले

जाने और सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से सीएम रेखा गुप्ता ने संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार जनता के सुझावों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर सैकड़ों सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। हमारी टीम उन सभी सुझावों की समीक्षा कर रही है ताकि दिल्ली की जनता को एक सर्वश्रेष्ठ बजट प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि यह बजट दिल्ली के नागरिकों का बजट होगा, जो राजधानी की समृद्धि और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, हम इसे जनता के बजट के रूप में पेश करेंगे, जिससे हर नागरिक को यह महसूस हो कि वह वास्तव में उनकी आकांक्षाओं का बजट है।

तर्ह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त, झुगगी-

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र का किया दौरा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को शालीमार बाग क्षेत्र के बौडब्ल्यू ब्लॉक का निरीक्षण किया और वहां के निवासियों के सामने आ रही समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आवश्यकतानुसार तुरंत सुधार कार्य शुरू करने पर जोर दिया और अधिकारियों को एक महीने के भीतर वृक्षारोपण अभियान पूरा करने का निर्देश दिया। गुप्ता ने कहा, जनता की छोटी-छोटी समस्याओं का भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाधान किया जाएगा। त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएगी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, जल बोर्ड, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ शालीमार बाग के बौडब्ल्यू ब्लॉक में साइट पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उन्हें जल्द हल करने के सख्त निर्देश दिए। हम जनता की छोटी से छोटी समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

झोपड़ी में रहने वाले परिवारों से भी हम मुलाकात करेंगे एवं युवाओं और अन्य वर्गों के साथ भी बातचीत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को हम पूरी तत्परता और ईमानदारी से पूरा करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों, खासकर महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार लाना और बजट को उन सभी वर्गों की जरूरतों के मुताबिक बनाना है।



औद्योगिक क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा।

राजधानी के औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान : उद्योग मंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार सभी 56 औद्योगिक क्षेत्रों के फैक्ट्री मालिकों और व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी। हर औद्योगिक क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं इसलिए सबके साथ अलग अलग मुलाकात करके समस्याओं का समाधान करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना चाहिए और दिल्ली सरकार एक शानदार नयी इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों से सुझाव लेकर बनाएंगे बजट बनाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बुधवार को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट कान्फ्लेव का आयोजन किया जिसमें दिल्ली की 300 मार्केट एसोसिएशन्स और इंडस्ट्री एसोसिएशन्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा मुख्य अतिथि थे।

सीटीआई चैयरमैन वृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उद्योग मंत्री के समक्ष 11 प्रमुख मांगों का एक मांगपत्र सौंपा। जिसमें बवाना, भोरगढ़, झिलमिल, बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लीज

● बोले, राष्ट्रीय राजधानी के लिए शानदार इंडस्ट्री पॉलिसी बनाएं

● व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों से सुझाव लेकर बनाएंगे बजट : सिरसा

होल्ड से फ्री होल्ड किया जाए। नरेला समेत अनेक बहुत सारी जगहों पर सर्कल रेट की विसंगतियां हैं, उनको ठीक किया जाए। मिनिमम वेजेज, पड़ोसी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की दरें, दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है, उनको तर्क संगत किया जाए। गोदामों के रखरखाव के लिए अलग वेयर हाउस पॉलिसी बनाई जाए। पिछली सरकार के दौरान 6 बाजारों के पुनर्विकास को घोषणा की गई थी, उसको जारी रखा जाए। दिल्ली में दुबई और चीन की तर्ज पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाए।

चांदनी चौक, सदर बाजार समेत ऐतिहासिक बाजारों के लिए अलग से स्कीम बननी चाहिए। व्यापारियों का माल देश विदेश में पहुंचे, उसके लिए दिल्ली बाजार पोर्टल बनाया जाए। दिल्ली नगर निगम का फैक्ट्री लाइसेंस खत्म किया जाए। ईज ऑफ बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए।

ईडब्ल्यूएस बच्चों के एडमिशन के लिए निकली लॉटरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

शिक्षा में दिल्ली सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। यह दावा शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के सभी निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लॉटरी से ड्रा के अवसर पर किया।

शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत दाखिले के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के कॉन्फ्रेंस रूम में 'ड्रॉ ऑफ लॉटरी' के जरिए



ईडब्ल्यूएस कोटे की लॉटरी के लिए बच्चे से बटन दबवाते शिक्षा मंत्री आशीष सूद।

ऑनलाइन लॉटरी निकली गई। इस अवसर पर आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में पहली बार लॉटरी की ये प्रक्रिया हजारों अभिभावकों और

● शिक्षा मंत्री ने दाखिले में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए प्रवेश ड्रा निकाला

पारदर्शी तरीके से तीन कैटेगरी नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के लिए बुधवार को ड्रॉ निकाला गया। गायत्री के पुत्र भावेश ने केजी और पहली क्लास के लिए 'ड्रॉ ऑफ लॉटरी' के लिए स्टैंड अलोन कंप्यूटर के बटन को दबा कर ड्रा की शुरुआत की।

शिक्षा निदेशक भी अपना फोन कमरे के अंदर लेकर नहीं गए और स्वयं में भी अपना फोन अंदर नहीं

आंबेडकर विश्वविद्यालय के चुनाव में एसएफआई को बहुमत हासिल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने आंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली छात्र परिषद (एयूडीएससी) के चुनावों में 45 में से 24 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया।

एसएफआई ने एक बयान जारी कर कहा कि छह साल के बाद आयोजित चुनावों में सभी परिसर के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें एसएफआई ने करमपुरा परिसर में महत्वपूर्ण बहुमत हासिल की, जबकि लोधी रोड और कुतुब

इंस्टीट्यूशनल एरिया परिसर में भी पहली बार जीत दर्ज की। कश्मीरी गेट परिसर में एसएफआई ने 16 सीट, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने चार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दो और निर्दलीय ने छह सीट जीतीं। करमपुरा परिसर में एसएफआई ने पांच सीट, आइसा ने दो, एबीवीपी ने एक और निर्दलीय ने चार सीट जीतीं। लोधी रोड परिसर में एसएफआई ने एक, निर्दलीय ने दो सीट जीती, वहीं एबीवीपी और आइसा खाता भी नहीं खोल पाए। कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया परिसर में एसएफआई ने दोनों

सांक्षिप्त समाचार

पालम 360 गांव के प्रधान पुलिस आयुक्त मिले

नई दिल्ली। पालम 360 गांव के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की और राजधानी की कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और पालम थाना को द्वारका जिला पुलिस के तहत हस्तांतरित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देती है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाया जाएगा।



डीयू की प्रो. रीना अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित

नई दिल्ली। उत्कृष्ट नवाचार, अनुसंधान कार्य और प्रौद्योगिकी विकास के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर (डॉ.) रीना चक्रवर्ती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में 8वें विजिटर्स अवार्ड, 2023 प्रदान किए थे। जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान पुरस्कार इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार वर्ष 2015 से भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार के लिए डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने उन्हें बधाई दी और कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ऐसे शोध को बढ़ावा देना होना चाहिए जो राष्ट्र की प्रगति में सहयोग दें। प्रो. चक्रवर्ती ने कहा कि विवि में उत्कृष्टता पैदा करने में कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अहम भूमिका रही है। विभाग में चल रहे शोध का अवलोकन करने के लिए कुलपति समय-समय पर विभाग का दौरा करते रहते हैं और संकल्प सदस्यों के साथ-साथ शोध छात्रों से भी बातचीत कर के उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि डीयू को यह पुरस्कार मिला है।

इमारत का हिस्सा बहने से दो लोग घायल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के जी.बी. रोड पर बुधवार को एक इमारत का एक हिस्सा ढह जाने से दो लोग घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उन्हें अपराह्न दो बजकर 32 मिनट पर एक इमारत का हिस्सा ढहने की सूचना मिली और बचाव दल को मौके पर भेजा गया। डीएफएस के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि एक महिला और एक पुरुष इसमें घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

दो महीनों में 61 भगोड़े गिरफ्तार: पुलिस

नई दिल्ली। पुलिस ने इस साल के पहले दो महीनों में देशभर से 61 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हत्या सहित अन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्ति शामिल हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि किसी व्यक्ति को भगोड़ा तब घोषित किया जाता है जब वह जांच के चरण में या सुनवाई के दौरान कानून की प्रक्रिया से बचता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर एक विशेष टीम भी गठित की गई है जो ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्होंने कहा, जनवरी 2025 से अब तक दलों ने 32 भगोड़ों का पता लगाया है, जिनमें हत्या के मामलों में शामिल तीन व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें बंगलुरु, पुणे और दिल्ली से पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ 2015 से ही फरार थे।

इंजीनियर रशीद की याचिका पर 7 को सुनाएगी फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद जन्म कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद को आगामी संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सात मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया। रशीद की ओर से अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा 27 फरवरी को दायर याचिका में इस आधार पर उन्हें राहत देने का अनुरोध किया गया है कि वह (रशीद) एक सांसद हैं और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद के आगामी सत्र में उन्हें उपस्थित होना आवश्यक है।

आप ने भाजपा को याद दिलाया 2500 का वादा

सिर्फ तीन दिन और...

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली को एक फ्लाईओवर पर पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है, सिर्फ तीन दिन और। आप कार्यकर्ताओं का उद्देश्य आठ मार्च तक महिलाओं को 2500 रूपए मासिक वित्तीय सहायता देने संबंधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के वादे को लेकर उस पर दबाव बनाना है। आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप नेता और पूर्व विधायक ऋतुराज झा ने



योजना के क्रियान्वयन में विलंब पर सवाल उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 30 जनवरी की टिप्पणी का हवाला दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2,500 रूपए देने की योजना पारित की जाएगी और आठ

दिल्ली को बनाएंगे नशा मुक्त : रविंद्र इंद्राज

● समाज कल्याण मंत्री ने स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में युवाओं से सहयोग की अपील की

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने दावा किया कि वह युवाओं के सहयोग से दिल्ली को नशा मुक्त बनाएंगे। उन्होंने इस काम में युवाओं से सहयोग की अपील की है। इंद्राज ने यह बात बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के अलीपुर स्थित



स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के वार्षिकोत्सव श्रद्धा तंरंग में वतौर मुख्य अतिथि यह बात कही।

इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश की दिशा, युवा निर्धारित करते हैं। आप सभी दिल्ली को बेहतर बनाने और

विकसित भारत-विकसित दिल्ली संकल्प को पूरा करने के लिए सुझाव दें। दिल्ली को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य युवाओं के सहयोग से ही पूरा हो सकता है। स्वामी श्रद्धानंद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इंद्राज ने कहा कि स्वामी का कहना था की देश को संवकों की जरूरत है, नेताओं की नहीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार इसी मूलमंत्र के साथ कार्य कर रही है।

इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रवीण गर्ग, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. डी बी भारद्वाज और संयोजक प्रतिभा राणा ने मंत्री का स्वागत किया और उनके संकल्प नशामुक्त दिल्ली, उज्ज्वल भविष्य के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया।

संजय वन का किला ऐतिहासिक विरासत : एलजी

● उपराज्यपाल ने किले की प्राचीर, कुएं के पुनरुद्धार और रॉक कैफे किया उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार दक्षिण दिल्ली स्थित संजय वन में ऐतिहासिक किले की प्राचीर और कुएं के पुरस्कार तथा रॉक कैफे के उद्घाटन किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा जहाँ इतिहास प्राचीन पत्थरों में गुंजाता है और प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। यह धरोहर न केवल दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यह संरचना, सदियों



तक गाद में दबी रही और केवल कुछ जर्जर बुर्ज ही दिखाई देते थे, अब अपनी पुरानी भव्यता में पुनर्जीवित हो चुकी हैं।

इसके वास्तुशिल्पीय स्वरूप को देखते हुए इसे 13वीं-14वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार, यह पृथ्वीराज चौहान के किले और महल का हिस्सा था। इसके पास स्थित ऐतिहासिक कुआँ भी संभवतः उसी युग का है।

इसके अलावा, 12वीं शताब्दी में बने किला राय पिथौरा और तोमर वंश के अन्य अवशेष भी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जो दिल्ली के गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं। इस धरोहर को फिर से जीवंत किया गया है, जिससे न केवल ऐतिहासिक महत्व को संरचनाओं का संरक्षण हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी संवारा गया है। अब यह हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस अमूल्य विरासत को संभालें, इसे स्वच्छ और संरक्षित रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सकें। लोगों, विशेष कर युवाओं से अधिक करीबों और बुनकरों द्वारा प्रदर्शित पारंपरिक हस्तशिल्प एवं

भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में है कृषि क्षेत्र की महती भूमिका: डॉ संगीता बलवंत

संवाददाता। गाजीपुर

जनपद में बुधवार को शहर स्थित पी.जी. कॉलेज में बी.एससी. (कृषि) सातवें सेमेस्टर के छात्रों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत संरक्षण कृषि: मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हेतु आधुनिक तकनीकें विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कृषि संकाय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वावधान में संपन्न हुई, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों, विषय-विशेषज्ञों, शोधार्थियों और छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की।

मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र सरकार की



प्राथमिकताओं में है, जिसे बजट में भी विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 5 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को पात्रता पूरी करने पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में

उभर रहा है, जिसमें कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। वर्तमान सरकार कृषि शिक्षा को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत कई नए कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कृषि उप निदेशक डॉ. अतिरिक्त सिंह ने कृषि सुधारों एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं, कृषि वैज्ञानिक डॉ. धर्मदेव कुमार सिंह ने मृदा क्षरण और कटाव को रोकने के उपायों पर प्रकाश

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत, जो 1965 से पहले खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भर था, हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भर बना। इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रो. (डॉ.) जी. सिंह ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (ऋक्षुध) को शामिल किया गया है। इसके तहत छात्रों को 20 सप्ताह तक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसमें एक सप्ताह कॉलेज कैम्पस में, पांच सप्ताह कृषि विज्ञान केंद्र में, तीन सप्ताह प्लांट हेल्थ क्लिनिक में, आठ सप्ताह किसानों के साथ गाँवों में व्यवहारिक प्रशिक्षण, तीन सप्ताह एग्री-इंडस्ट्री में प्रशिक्षण और एक सप्ताह प्रोजेक्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण शामिल होगा।

परीक्षा केवल प्रशासनिक सेवा में चयन का माध्यम मात्र नहीं: प्रो. त्रिपाठी

संवाददाता। प्रयागराज

मंगल पांडे स्वाध्याय मण्डल द्वारा बुधवार को बैंक रोड स्थित सागर अकादमी सभागार में यूपीएससी परीक्षाओं हेतु सेमिनार एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यूपीएससी लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सही रणनीति पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया से अवगत कराना था। इसके पश्चात मंगल पाण्डेय स्वाध्याय मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में प्रो गिरीश चंद्र त्रिपाठी पूर्व कुलपति उपस्थित रहे। साथ ही पूर्व आईपीएस जुगल किशोर तिवारी मुख्य वक्ता और पूर्व आईजी के



पी सिंह विशिष्ट अतिथि ने भी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रतिष्ठित सागर आईएस एकेडमी के निदेशक ओ पी शुक्ला भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि प्रो गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि यह परीक्षा न केवल प्रशासनिक सेवा में चयन का माध्यम है। बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करती है। उन्होंने अभ्यर्थियों को अनुशासन निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने की सलाह दी। प्रो त्रिपाठी ने बताया कि संस्था समाज

और संस्थान में एक संबंध होता है और जिस समाज में व्यक्ति लेने से अधिक समाज को देता है वह समाज आगे बढ़ता है और जिस समाज में व्यक्ति समाज से अधिक लेता है वह समाज पीछे चला जाता है जिसमें किसी का भी विकास नहीं होता है। मुख्य वक्ता जुगल किशोर तिवारी ने यूपीएससी परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने प्रारंभिक मुख्य और साक्षात्कार परीक्षाओं के स्वरूपों पर जानकारी देते हुए एनसीईआरटी पुस्तकों की उपयोगिता पर जोर दिया।

प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान को प्रदेश में मिला द्वितीय पुरस्कार



सोनभद्र। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी जनपदों में अच्छे एवं नवाचार कार्य किए जाने का निर्देश पंचायत राज निदेशालय द्वारा दिया गया था। जिसमें होटल दयाल गेटवे में सभी 75 जिलों के कंसल्टेंट, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप निदेशक पंचायत ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में 29 जिलों ने अपने यहां कार्याय हुए नवाचार का प्रस्तुतीकरण किया। जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण द्वारा बताया गया कि सोनभद्र में चलाए जा रहे प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें बताया गया कि आज सभी

जगह की मूल समस्या प्लास्टिक की है क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रयोग करने के बाद हम खुले वातावरण में फेंक देते हैं या तो उस प्लास्टिक में हम अन्य कूड़े को भी भर कर फेंक देते हैं जिससे कि निस्कारण में कूड़े को सैरीगेट करना सबसे कठिन चुनौती बन जाती है। इस चुनौती को आसान करने के लिए सोनभद्र में नवाचार के द्वारा प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान चलाया गया, जिसमें घर पर बोरी लगाकर प्रयोग किए गए प्लास्टिक को उसी में रखे जाने हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

पीने के लिए उपलब्ध कराया जाय शुद्ध पेयजल: मंडलायुवत

● आयुक्त विन्ध्याचल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक संवाददाता। सोनभद्र

आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल मौरजापुर, नोडल अधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री के निरीक्षण की अनुपालन आख्या एवं सी0एम0 डैशबोर्ड उपलब्ध फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं जन शिकायत की मासिक समीक्षा बैठक जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ की गयी। इस दौरान मण्डलायुक्त ने कहा कि जिला संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती मरीजों का ईलाज बेहतर तरीके से करने के साथ ही अस्पताल से ही दवा उपलब्ध करायी जाये। प्रभारी मंत्री द्वारा पूर्व में सम्बन्धित विभाग को महुआ, चिचौली आदि के पौधे लगाने के अनुपालन की समीक्षा की गयी, जिस पर बताया गया कि पौधों का रोपण किया जा चुका है, कुछ स्थानों पर पानी के



अभाव में पौध रोपण करना शेष है। पानी उपलब्ध होने पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद में परिषद विद्यालयों के बच्चों को जूते,मोजे,बैग,धराराशि आदि का लाभ न मिलने को शिकायत मिली है। जिस पर बीएसए ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुछ विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का आधार न बन पाने की वजह से इन लाभों से वंचित हैं, जिसके लिए सम्बन्धित विभागों को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्र प्रेषित किया गया है। मण्डलायुक्त ने कहा कि पी0एम0 कुसुम योजना के तहत किसानों को

स्थल का चयन करते हुए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी शादी करायी जा रही है वह प्राथमिकता में से एक है, इसलिए शादी के लिए जोड़ों का आवेदन के बाद सत्यापन का कार्य गंभीरता पूर्वक किया जाये। भ्रमण के दौरान मनबसा गांव में कोटेदार द्वारा लाभार्थियों से 10 रुपये लेने की शिकायत मिली है, जिला पूर्व अधिकारी द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण व निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डलायुक्त ने स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े परियोजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाया जाये, मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाये, पंचायत राज विभाग की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक बाजार लगने वाले स्थल को चिन्हित करते हुए वहां पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने के साथ ही लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक भी किया जाये। शहरों में भी

कैम्प लगाकर जानकारी दी जाये, जनपद में स्थापित गो-आश्रय स्थलों में आगामी गर्मी को देखते हुए गोवर्षों के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आवास सर्वे के कार्य में तेजी लाया जाये। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाये, पंचायत राज विभाग की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने कहा कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक बाजार लगने वाले स्थल को चिन्हित करते हुए वहां पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने के साथ ही लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक भी किया जाये। शहरों में भी

विवक न्यूज

याचिका में फर्जीवाड़ा, याची वकील से कोर्ट ने मांगी सफाई प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दायित्व करने की प्रक्रिया होने वाले में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कोर्ट ने याची अधिकाता संतोष कुमार से दो दिन में सफाई मांगी है कि यह कैसे हुआ है। गांव सभा के अधिकाता दीपक गौर ने आरोप लगाया कि याचिका की प्रति उसे नहीं दी गई और पावती दर्ज कर दायित्व कर दी गई। उसकी पावती फर्जी दर्ज की गई है। याचिका की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन कुमार निगम ने जालौन की सफाई उर्फ सफाई देवी की याचिका पर दिया है। जब याचिका सुनवाई के लिए पुकारा गई तो याची अधिकाता संतोष कुमार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी गांव सभा के अधिकाता दीपक गौर ने आपत्ति की कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं दी गई है किन्तु याचिका पर उन्हें प्राप्त हो गई है की प्रविष्टि दर्ज है। जो कि पूर्णतया फर्जी है। विपक्षी अधिकाता को याचिका की प्रति देने के लिए सफाई ही नहीं किया गया इसलिए कोर्ट ने याची अधिकाता से सफाई मांगी है। कोर्ट ने निबंधक अलुपाल को 48 घंटे में याची अधिकाता संतोष कुमार को आदेश की जानकारी देने का आदेश दिया है।

हर वर्ष 28 मिलियन से ज्यादा होती है सर्जरी प्रयागराज। मोतिदाबिंद की सर्जरी विश्व स्तर पर सबसे आगे सर्जरी है। जिसमें हर साल 28 मिलियन से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं लेकिन केवल दस से पंद्रह फीसद सर्जरी को ही आधुनिक ऑप्टिकल आईओल मिल रहे हैं जो विश्व स्तर पर एडिटेड ग्लास लेंस और प्रेखायोजिता की समस्याओं को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह बाते गॉन्सन एंड गॉन्सन मेडिकल के सर्जिकल विजन इंडिया एवं दक्षिण एशिया के कंटी नैनेजर ब्रुनिंग शाखा ने कही। बताया कि गॉन्सन एंड गॉन्सन ने देश में नया इन्ट्रोड्युसिंग लेंस लाय किया है। यह नई नई पीढ़ी का लेंस पूरी तरह से रिफ्रेक्टिव डिजाइन से बना है जो बिना किसी रुकावट के साफ और बेदरतीन नजर देता है। आंखों को देखभाल में दुनिया की जानी मानी कंपनी ने आगे भारत में अपना इन्ट्रोड्युसिंग लेंस आईओल लाय करवा के घोषणा की। यह लेंस मोतिदाबिंद के ऑपरेशन में इस्तेमाल लेने वाली लेंस है। जो पूरी तरह से रिफ्रेक्टिव तकनीक पर आधारित है और उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रेखायोजिता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत परिणय बंधन में बंधे युगल

संवाददाता। अंबेडकर नगर

प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरत मन्द एवं निर्धन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं एवं परम्पराओं व रीति रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह करारक समाज के सभी वर्गों में सर्व धर्म सम्भाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। निदेशालय, समाज कल्याण, 3030 लखनऊ द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकरनगर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1158 जोड़ों का लक्ष्य



निर्धारित किया गया है। 05.03.2025 को राजकीय हवाई पट्टी, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जिसमें विकास खण्ड अकबरपुर के 140, विकास खण्ड टाण्डा के 134, विकास खण्ड बसखारी के 72 एवं नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के 09, नगर पंचायत इल्टफातगंज के 3, नगर पालिका टाण्डा के 4 एवं नगर पालिका अकबरपुर के 24 कुल 386 पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया, जिसमें 01

मुस्लिम जोड़े का निकाह भी सम्मिलित है। कार्यक्रम में श्री अविनाश सिंह जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर, आनन्द कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के अतिरिक्त मिथिलेश त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, रामशंकर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता, संजय निषाद, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी आदि विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित रहे। जिलाधिकारी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई



बीजपुर, सोनभद्र। बुधवार को स्थानीय थाना परिसर में रमजान माह व होलिका दहन, होली पर्व के मद्देनजर सीओ दुर्गा प्रदीप सिंह चंदेल के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों व सभ्रत व्यक्तियों की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान सीओ श्री चंदेल ने लोगों को आश्चर्य किया कि यदि त्योहार के दौरान कोई भी अराजक तत्व खलल डालने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ विधिक कार्यवाई करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभाओं में कुल 63 स्थानों पर होलिका दहन किया जाता रह है। रमजान माह में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन ही होली का पर्व होगा इसलिए हिन्दू व मुस्लिम समुदाय के लोग पूर्व की भाँति सौहार्द बनाकर ही अपने अपने त्यौहारों को मनाकर शासन का सहयोग करेंगे।

जल निगम की टूटी पाइप से जलभराव को लेकर प्रदर्शन



सकलडीहा, चन्दौली। मोबाइल कंपनी की केबिल डालते समय मंगलवार की देर शाम जल निगम की पाइप क्षतिग्रस्त होगयी। कंपनी के टेकेदार की ओर से टूटी पाइप का मरम्मत नहीं कराये जाने से सड़क पर जलभराव की स्थिति होगयी। जिसके कारण दुकानों पर ग्राहकों के आने जाने में समस्या और राहगीरों की परेशानी को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने टूटी पाइप की मरम्मत नहीं कराये जाने पर आन्दोलन की चेतावनी के साथ कोवाली में एफआईए पाइप को तोड़ दिया पर बहने से ही जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

टेकेदार की ओर से जगह जाहद केबिल डालने के लिये मशीन से खोदाई किया जा रहा है। खोदाई के कारण जल निगम की पाइप कई जगह क्षतिग्रस्त होगयी है। यही नहीं कई जगह गड्डा खोदकर छोड़ दिये जाने से रात में नगर लोग निभाव हो रहे है। दो दिन पूर्व सकलडीहा इंटर कॉलेज गेट के सामने केबिल डालने के लिये खोदाई के दौरान जल निगम की पाइप क्षतिग्रस्त हो गया। टेकेदार की ओर से मरम्मत कराये नहीं जाने के कारण सुबह जल निगम की क्षतिग्रस्त पाइप से पानी सड़क पर बहने से ही जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

अनियंत्रित डम्फर ने पिकअप को मारी टक्कर,चार की मौत, छह घायल



चित्रकूट। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर शिवरामपुर कस्बे के पास पिकअप को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पिकअप में सवार चार महिलाओं की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हैं सभी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवरामपुर में भर्ती कराया गया है। यह घटना बरुआ नदी पुल के पास बुधवार की सुबह करीब पांच बजे हुई। पिकअप यात्रियों को लेकर प्रयागराज से जनपद बांदा के कालिंजर जा रही थी। हाईवे पर ओवर टेक करने के दौरान किसी अज्ञात वाहन ने पिकअप में टक्कर मार दी जिससे बड़े पलट गया। जिससे उसमें सवार यात्रियों में चौर पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे वाहनों के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवरामपुर में भर्ती कराया। जिसमें बांदा थाना कालिंजर के गाँडियाँ निवासी 60 वर्षीय कुसुमा पत्नी हरीराम, सड़ा निवासी 60 वर्षीय केशर पत्नी श्रीकेशन व 21 वर्षीय पुत्री सपना और मध्य प्रदेश जिला पन्ना थाना चंद्रा के खरबा निवासी सुनील की 14 वर्षीय पुत्री मनु की मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि 62 वर्षीय शकुंतला, 65 वर्षीय किशन, 35 वर्षीय वंदना और 16 वर्षीय भोले का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आगामी त्यौहारों को संकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम-एसपी ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक

संवाददाता। चित्रकूट

जिलाधिकारी शिवशरणपा जीएन की अध्यक्षता में एवं पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार की उपस्थिति में आगामी रमजान, होलिका दहन, होलीकोउत्सव, गुड फ्रडडे, चैत्र नवरात्रि, ईद उल फितर, चैत्र श्री रामनवमी आदि त्यौहारों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संकुशल संपन्न कराने हेतु दोनों समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ बैठक जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि 13 मार्च को होलिका दहन एवं 14 मार्च को होलिका उत्सव का पर्व है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित फीडबैक लिए एवं निर्देशित किया कि किसी प्रकार का विवाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों विद्युत को निर्देशित किया कि होलिका स्थल पर तार ना लटकता रहे एवं होलिका दहन कमेटी को भी निर्देशित किया कि ऐसे स्थलों पर होलिका दहन न करें। अधिशासी अधिकारी कर्वा, मऊ, मानिकपुर, राजापुर को निर्देशित किया कि होलिका दहन स्थल एवं मरिजद धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई प्रकाश पानी



आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीपीएससी,पीएससी पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने जल संस्थान को निर्देशित किया कि पानी की सप्लाई लगातार रहनी चाहिए एवं जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि 15 मार्च को होलिका दहन के दिनों में जल आपूर्ति को निरंतर बनाए रखा जाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया लगातार छापा मारी कर मिलावट खोरो को पकड़े किसी प्रकार की खाद्य सामग्री में मिलावट नहीं होने पाए

।उन्होंने सहायक सभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि अधिक वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि दोनों समुदायों के त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार हैं उसकी तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में 803 होलिका दहन स्थल है। कहा कि अन्य जनपदों में होली पर शिव बारात, राम बारात निकाली जाती है लेकिन अपने जनपद में यहां होलिका दहन ही होती है। कहा कि सुरक्षा समिति होलिका समिति का नाम अवश्य बनाकर भेजे होलिका स्थल के लिए पुलिस कर्मियों को इ्यूटी लगा दिया गया है इसके साथ ही साथ निगरानी भी करेंगे। कहा

कि जिन पुलिस कर्मियों की इ्यूटी लगाई गई है वह होली के दिन मुस्लीमों के साथ इ्यूटी करेंगे। कहा कि लाउडस्पीकर डीजे होली व रमजान पर लोगों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निर्धारित मानक ध्वनि से तेज बजाने को अनुमति कदापि न दी जाए तथा रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर आदि को बजाने को अनुमति नहीं होगी। वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 144 यानी बीएनएस की धारा 163 प्रभावी है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर जो बच्चे स्टंट करते हैं बड़े बच्चे बच्चों को रोकें। सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि ओवरलोडिंग आंदो जीप आदि पर नहीं होनी चाहिए, 12 मार्च तक विशेष चेंकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई कर सीज करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपात त्रिपाठी, उप जिला अधिकारी कर्वा सुश्री पूजा साहू, मऊ सीवय यादव ,मानिकपुर मोहम्मद जसीम ,उप जिलाधिकारी प्रशिक्षु सुश्री हर्षिता देवड़ा, पुलिस क्षेत्राधिकार मऊ यामीन अहमद, राजापुर जय करण सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव मिश्रा सहित पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी योग के नवीन आयामों को जन्म देगी: कुलपति

संवाददाता। चित्रकूट

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में चल रही दर्शनशास्त्र विभाग के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किये। संगोष्ठी कक्ष में आयोजित सत्र की अध्यक्षता डॉ0 ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडेय ने कहा कि योग जैसे सार्वसामयिक विषय पर आयोजित होने वाली यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी निश्चित रूप से योग के नवीन आयामों को जन्म देगी जिसके माध्यम से न केवल वैदिक बल्कि मानवीय समस्याओं का समाधान कुलपति समाधान संभव होगा। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी के माध्यम से देश-विदेश में योग के एक नए युग का सूत्रपात होगा। अमरकंटक विश्वविद्यालय से



पधारे प्रो0 गोविंद प्रसाद मिश्र ने कहा कि प्रज्ञा अपराध जैसे अपराधों को योग के द्वारा ही निवृत्ति कर हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रज्ञावान बना सकते हैं। महामत्सा योधी काशी विश्वपीठ वाराणसी से पधारे डॉ0 अम्बरीशराराय ने आसन एवं प्राणायाम के साथ-साथ वैराग्य योग एवं क्रिया योग की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इंद्रियों का रिश्ता मन से है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधार्थी राजाराम ने पतंजलि योग एवं हठयोग में समाधि के स्वरूप पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी विशेष कुमार सिंह ने योग में समरता के अध्ययन विषय पर अपना विचार प्रकट करते हुए सामाजिक एकरूपता पर बल दिया पतंजलि विश्वविद्यालय से पधारे राजेश कुमार ने परंपरागत योग में प्राणायाम के अनुशीलन पर अपने विचार प्रस्तुत किये। पतंजलि विश्वविद्यालय से पधारे संजना ने प्राणायाम के महत्व एवं लाभ के बारे में अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त समानांतर सत्र में लगभग 30 से अधिक वक्ताओं ने अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया।

आकाश की सुरक्षा

‘आत्मनिर्भर भारत पहल’

भारत को अपने आकाश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए क्योंकि विपक्षी तेजी से अगली पीढ़ी के विमानों का उन्नीकरण कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वह ‘आत्मनिर्भर भारत पहल’ के अंतर्गत तेजी से आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन स्थापित कर रही है। भारतीय वायुसेना की क्षमता संवर्धन हेतु उच्चाधिकार समिति की हालिया रिपोर्ट में प्रमुख प्राप्ति क्षेत्रों की पहचान के साथ बलों की क्षमता बढ़ाने व उसकी कमियों को संबोधित करने के सुझाव दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना वर्तमान समय में 31 लड़ाकू स्क्वाड्रनों का संचालन कर रही है जो उसकी 42 स्क्वाड्रन की स्वीकृत क्षमता से बहुत कम है। हल्के लड़ाकू विमान-एलसीए एमके1ए प्राप्त करने में विलंब तथा धीरे-धीरे पुराने पड़ रहे ज़ुआर, मिग-29यूपीजी और मिराज-2000 को हटाने से नए अधिग्रहणों की आवश्यकता सामने आती है। हाल ही में एलसीए एमके1ए, एलसीए एमके2 और पांचवीं पीढ़ी के एडवॉंस्ट मोडियस एयक्राफ्ट-एमसीए का उत्पादन तेज किया गया है। इसके साथ ही आपरेशनल क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त हवाई शोत्र चेतवानी व नियंत्रण-एडवॉंस्ट मोडियस विमानों, उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाले तथा उत्कृष्ट मिसाइल सिस्टमों की आवश्यकता बताई गई है। कमेटी ने रक्षा पीएसयू व डीआरडीओ के प्रयासों में योगदान के लिए निजी क्षेत्र को भूमिका पर जोर दिया है ताकि एयरोस्पेस विनिर्माण में उत्पादन क्षमता बढ़ा कर उसे बेहतर बनाया जा सके।



धोमी गति के कारण लड़ाकू क्षमता में कमियां पैदा हुई हैं क्योंकि विरोधी, खासकर चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी वायुसेनाओं के उन्नीकरण के लिए पांचवीं पीढ़ी और यहां तक कि छठी पीढ़ी के विमान भी प्राप्त कर रहे हैं। जटिल खरीद प्रक्रिया तथा निर्णय लेने की त्वरित गति की कमी के कारण महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में देर होती है जिससे वायुसेना की शक्ति घटती है। हालांकि, स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं में प्रगति की गई है, पर अब भी उच्चस्तरीय तकनीकों, जैसे जेट इंजनों, उत्कृष्ट वैमानिकी तथा स्टोल्थ क्षमताओं के विकास में कमियां बनी हुई हैं। रक्षा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय आबंटन आधुनिकीकरण लक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए ताकि स्वदेशी परियोजनाओं के साथ तत्काल अधिग्रहण के लिए उपयुक्त फंडिंग सुनिश्चित की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्देश दिए हैं कि समिति को संस्तुतियों को सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए ताकि और विलंब से बचा जा सके। सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि एएमसीए कार्यक्रम का समयबद्ध क्रियान्वयन हो तथा एचएएल की उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि कर उसे हर साल आवश्यक लड़ाकू विमान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाए। इसके साथ ही एक सुधरी खरीद प्रक्रिया की भी जरूरत है ताकि नौकरशाही के कारण होने वाले विलंब को समाप्त किया जा सके जो तेजी से अनुमतियों एवं अधिग्रहणों के लिए जरूरी है। विश्व की प्रमुख विमान निर्माता कंपनियों से सहयोग मजबूत करने से उत्कृष्ट तकनीक प्राप्त की जा सकती है तथा स्वदेशी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना हो सकती है। इनसे आधुनिकीकरण तेज करने में सहायता मिलेगी। नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों तथा ढांचागत समर्थन से निजी रक्षा विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने से विमान क्षेत्र के उत्पादकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उच्चाधिकार समिति की संस्तुतियों से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता रेखांकित होती है। इसके साथ ही व्यवस्थागत चुनौतियों से निपटना तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से खोजन को बढ़ावा देना भी जरूरी है। वास्तव में भारत को एक युद्ध के लिए तैयार तथा आत्मनिर्भर वायुसेना की आवश्यकता है जो वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आज पहले के किसी भी समय की तुलना में आधुनिक एवं अत्याधिक सक्षम वायुसेना सर्वाधिक आवश्यक है।

म्यांमार में सैनिक शासन को चुनौती

म्यांमार के गृहयुद्ध में प्रतिरोधी बलों ने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन और रूस के समर्थन से सैनिक शासन का प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों पर कब्जा बना हुआ है।



अशोक के. मेहता
(लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं)

पिछले सप्ताह केन्द्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत मणिपुर की स्थितियों पर एक समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने म्यांमार और सीमावर्ती क्षेत्रों के उन व्यापार मार्गों पर भी चर्चा की जिन पर अब म्यांमार के सैनिक शासन का नियंत्रण नहीं है। अतीत पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि 1962 तक म्यांमार पर सेना के जनरलों का एकछत्र शासन था। हालांकि, फरवरी, 2021 में हुआ चौथा सैनिक विद्रोह सबसे लंबा था, पर उसे पहली बार बहुत बड़े प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। बर्मा लोग-‘बीमार’ विपक्षी बलों में शामिल हो गए हैं जिनमें नस्ली सशस्त्र संगठन-एओ, राष्ट्रीय एकीकृत सरकार-एनयूजी के अंतर्गत पीपुल्स डिफेंस फ़ोर्स-पीडीएफ स्थानीय मिलिशिया तथा विद्रोही समूह शामिल हैं। ये सभी समूह सैनिक शासन को परजित करने के लिए एकजुट हो गए हैं। म्यांमार में सैनिक शासन के अंतर्गत संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और वह उसका लाभ उठा रहा है। संगठित अपराध के कारण 2 बिलियन डालर के साइबर धोखाधड़े व अन्य धोखाधड़ी वाले अपराध हुए हैं। अनेक निरपराध भारतीय इन अपराधों में अनजाने सहयोगी या इनके शिकार बन चुके हैं।

इसके पहले म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ विरोध इतना संगठित नहीं था। उसकी यह सफलता इस तथ्य के बावजूद है कि कोई एकीकृत कमांड नहीं है तथा उनके आपरेशनों के बीच समन्वय की कार्यवाही ‘श्री बद्रहूद एलायंस’ जैसे संगठनों द्वारा की जा रही है जिसके चलते आपरेशन 1027 तीन ईएओ-टीएनएएए, एमएनडीएए तथा एए द्वारा शुरू किए गए हैं। म्यांमार में सैनिक शासन का विरोध करने वाले इन सशस्त्र संगठनों में सैनिक रूप से अराकान आर्मी-एए सबसे मजबूत है। वह दक्षिण के राखीन प्रांत में सक्रिय है, जबकि अन्य दो ईएओ उत्तरी शान राज्य में सक्रिय हैं। विद्रोही बलों के आपरेशन कोडोम 1027 का संबंध उत्तर में व्यापक अभियान शुरू करने की तारीख 27 अक्टूबर, 2023 से है।

चीन म्यांमार में दोमुंही भूमिका निभा रहा है। वह सैनिक शासन का समर्थन करने



के साथ ही कुछ ईएओ का समर्थन भी कर रहा है। हालांकि, निकट अतीत में उसने नीतिगत बदलाव करते हुए सैनिक शासन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। लेकिन चीन की घोषणाओं भ्रामक और धोखाधड़ी से भरी हैं, इसलिए चीन की घोषणाओं के बजाय उसके कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जमीनी स्तर पर गौर करें तो म्यांमार में गृहयुद्ध का चौथा साल चल रहा है। सैनिक शासन की काफी जमीन छिन गई है, लेकिन वह किसी प्रकार भी हार के करीब नहीं है।

यदि सैनिक टकराव का व्यापक आंकलन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि सैनिक शासन का म्यांमार के 21 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा है जिसमें ‘बीमार’ का महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र इरावडी शामिल है। इसके साथ ही सैनिक शासन के नियंत्रण में नई राजधानी नैपीडा, यंगून और मांडले शामिल हैं जो दो सबसे बड़े शहर हैं। इसके तीन ईएओ-टीएनएएए, एमएनडीएए तथा एए द्वारा शुरू किए गए हैं। केवल एक शासन का विरोध करने वाले इन सशस्त्र संगठनों में सैनिक रूप से अराकान आर्मी-एए सबसे मजबूत है। वह दक्षिण के राखीन प्रांत में सक्रिय है, जबकि अन्य दो ईएओ उत्तरी शान राज्य में सक्रिय हैं। विद्रोही बलों के आपरेशन कोडोम 1027 का संबंध उत्तर में व्यापक अभियान शुरू करने की तारीख 27 अक्टूबर, 2023 से है।

चीन म्यांमार में दोमुंही भूमिका निभा रहा है। वह सैनिक शासन का समर्थन करने के साथ ही कुछ ईएओ का समर्थन भी कर रहा है। हालांकि, निकट अतीत में उसने नीतिगत बदलाव करते हुए सैनिक शासन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। लेकिन चीन की घोषणाओं भ्रामक और धोखाधड़ी से भरी हैं, इसलिए चीन की घोषणाओं के बजाय उसके कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जमीनी स्तर पर गौर करें तो म्यांमार में गृहयुद्ध का चौथा साल चल रहा है। सैनिक शासन की काफी जमीन छिन गई है, लेकिन वह किसी प्रकार भी हार के करीब नहीं है। यदि सैनिक टकराव का व्यापक आंकलन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि सैनिक शासन का म्यांमार के 21 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा है जिसमें ‘बीमार’ का महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र इरावडी शामिल है। इसके साथ ही सैनिक शासन के नियंत्रण में नई राजधानी नैपीडा, यंगून और मांडले शामिल हैं जो दो सबसे बड़े शहर हैं। इसके तीन ईएओ-टीएनएएए, एमएनडीएए तथा एए द्वारा शुरू किए गए हैं। केवल एक शासन का विरोध करने वाले इन सशस्त्र संगठनों में सैनिक रूप से अराकान आर्मी-एए सबसे मजबूत है। वह दक्षिण के राखीन प्रांत में सक्रिय है, जबकि अन्य दो ईएओ उत्तरी शान राज्य में सक्रिय हैं। विद्रोही बलों के आपरेशन कोडोम 1027 का संबंध उत्तर में व्यापक अभियान शुरू करने की तारीख 27 अक्टूबर, 2023 से है।

भारत म्यांमार में दोमुंही भूमिका निभा रहा है। वह सैनिक शासन का समर्थन करने के साथ ही कुछ ईएओ का समर्थन भी कर रहा है। हालांकि, निकट अतीत में उसने नीतिगत बदलाव करते हुए सैनिक शासन को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। लेकिन चीन की घोषणाओं भ्रामक और धोखाधड़ी से भरी हैं, इसलिए चीन की घोषणाओं के बजाय उसके कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जमीनी स्तर पर गौर करें तो म्यांमार में गृहयुद्ध का चौथा साल चल रहा है। सैनिक शासन की काफी जमीन छिन गई है, लेकिन वह किसी प्रकार भी हार के करीब नहीं है। यदि सैनिक टकराव का व्यापक आंकलन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि सैनिक शासन का म्यांमार के 21 प्रतिशत क्षेत्र पर कब्जा है जिसमें ‘बीमार’ का महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र इरावडी शामिल है। इसके साथ ही सैनिक शासन के नियंत्रण में नई राजधानी नैपीडा, यंगून और मांडले शामिल हैं जो दो सबसे बड़े शहर हैं। इसके तीन ईएओ-टीएनएएए, एमएनडीएए तथा एए द्वारा शुरू किए गए हैं। केवल एक शासन का विरोध करने वाले इन सशस्त्र संगठनों में सैनिक रूप से अराकान आर्मी-एए सबसे मजबूत है। वह दक्षिण के राखीन प्रांत में सक्रिय है, जबकि अन्य दो ईएओ उत्तरी शान राज्य में सक्रिय हैं। विद्रोही बलों के आपरेशन कोडोम 1027 का संबंध उत्तर में व्यापक अभियान शुरू करने की तारीख 27 अक्टूबर, 2023 से है।

फैक्ट्रियों को प्रतिरोधी बलों द्वारा नष्ट करना या उन पर कब्जा करना सेना के लिए बड़ा धक्का होगा, लेकिन इसके बावजूद यह सैनिक शासन को पराजित करने के लिए काफी नहीं है। पीडीएफ को स्वयं को बटालियन-ब्रिगेड संरचनाओं में संगठित करना चाहिए जिनका कमांड ढांचा रणनीतिक रूप से जमीन पर कब्जा कर उसे अपने पास बनाए रखने तथा हवाईअड्डों जैसे रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा करने में सक्षम हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दो स्थाई सदस्य चीन और रूस ‘असीम साझेदार’ होने के बावजूद सैनिक सहयोगी नहीं हैं। ये दोनों म्यांमार में सैनिक शासन का समर्थन कर रहे हैं। रूस अब मुख्य सैनिक सप्लायर है और 2021 से उसने 406 मिलियन डालर के सैनिक उपकरण सप्लाई किए हैं।

सैनिक शासन सुप्रीमो वरिष्ठ जनरल मिन आंग हिलांग ने पिछले साल रूस की यात्रा की थी जिसके लिए चिकित्सकीय जांच का बहाना बनाया गया था। रूस ने 6 एएसयू 30 विमान सप्लाई किए जिसके जवाब में 6 बर्मा हाथी मास्को भेजे गए। म्यांमार के विद्रोही समूहों में अब महिलाओं की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है, हालांकि वे मुख्यतः सहायक भूमिकाओं में हैं। इसके पहले के जन-विद्रोहों में महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत होती थी। इस बार अनिवासी म्यांमार नागरिकों का जन-विद्रोह को समर्थन

अब बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा पहले कभी नहीं रहा है। जनता के लोकतांत्रिक बलों-पीडीएफ में भर्ती बढ़ गई है तथा अनेक विदेशी शक्तियां भी उनका समर्थन कर रही हैं। पीडीएफ को प्रतीक रूप से ‘तरबूज’ कहा जा रहा है जो बाहर हरा और भीतर लाल होता है। म्यांमार के इस प्रतीक में जहां हरा रंग जन-सैनिकों की वर्दी का नैतिकता की कमी से उनकी युद्ध क्षमता प्रभावित हुई है। सरकारी सेनाओं में हाताहतों की संख्या बहुत अधिक है, पर उनके क्रोध आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। सैनिक शासन जमीनी स्तर पर नियंत्रण के झूठे दावे करते हैं और वे कुछ फर्जी इकाइयों की उपस्थिति बताते रहते हैं। सेना की अधिकांश सप्लाई लाइनें नष्ट हो चुकी हैं जिसके कारण उसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में सैनिक शासन का सारा आगमन अब वायुमार्ग तक सीमित है और विमानों से किए जवाबी हमलों में सिविलियन नागरिक बड़ी संख्या में हाताहत

हुए हैं। भगोड़े सैनिकों के कारण प्रतिरोधी बल मजबूत हुए हैं क्योंकि भगोड़े अपने साथ हथियार और अपना कौशल भी लाते हैं। म्यांमार के विद्रोही समूहों में अब महिलाओं की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है, हालांकि वे मुख्यतः सहायक भूमिकाओं में हैं। इसके पहले के जन-विद्रोहों में महिलाओं की संख्या केवल 10 प्रतिशत होती थी। इस बार अनिवासी म्यांमार नागरिकों का जन-विद्रोह को समर्थन अत्यधिक है और ऐसा पहले कभी नहीं रहा है। जनता के लोकतांत्रिक बलों-पीडीएफ में भर्ती बढ़ गई है तथा अनेक विदेशी शक्तियां भी उनका समर्थन कर रही हैं। पीडीएफ को प्रतीक रूप से ‘तरबूज’ कहा जा रहा है जो बाहर हरा और भीतर लाल होता है। म्यांमार के इस प्रतीक में जहां हरा रंग जन-सैनिकों की वर्दी का नैतिकता की कमी से उनकी युद्ध क्षमता प्रभावित हुई है। सरकारी सेनाओं में हाताहतों की संख्या बहुत अधिक है, पर उनके क्रोध आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। सैनिक शासन जमीनी स्तर पर नियंत्रण के झूठे दावे करते हैं और वे कुछ फर्जी इकाइयों की उपस्थिति बताते रहते हैं। सेना की अधिकांश सप्लाई लाइनें नष्ट हो चुकी हैं जिसके कारण उसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में सैनिक शासन का सारा आगमन अब वायुमार्ग तक सीमित है और विमानों से किए जवाबी हमलों में सिविलियन नागरिक बड़ी संख्या में हाताहत

ड्रोन आतंकवाद: पाकिस्तान की नई चाल

पाकिस्तान द्वारा छोटे ड्रोन का उपयोग कर हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, भारत के सामने एक नया और गंभीर खतरा बन चुकी है।

अभिषेक गुप्ता

(लेखक, राजनीतिक विश्लेषक हैं)



आधुनिक युद्ध अब सिर्फ भूमिगत लड़ाई तक सीमित नहीं है अब यह आसमान और डिजिटल दुनिया तक भी फैल गया है। पाकिस्तान द्वारा छोटे ड्रोन का उपयोग कर हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, भारत के सामने एक नया और गंभीर खतरा बन चुकी है। चीन के समर्थन से, पाकिस्तान इन ड्रोन को भारतीय हवाई क्षेत्र में भेजकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती एवं संवेदनशील राज्यों में। रात के अंधेरे में ये ड्रोन अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे सामान्य रडार सिस्टम इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते। यह भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनता जा रहा है। भारतीय सेना ने इस खतरे

को समझते हुए अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। अब सेना कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को पकड़ने और नष्ट करने के लिए लो-लेवल लाइटवेट रडार और नवीनतम एंटी-ड्रोन तकनीक हासिल कर रही है। ड्रोन का प्रयोग बीते समय में केवल निगरानी के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह आतंकवाद और संगठित अपराध के लिए एक सस्ता और कारगर हथियार बन चुका है। पाकिस्तान में चलने वाले कमरिशल क्राइडकॉन्ट्र ड्रोन से लेकर कस्टम-बिल्ट यूएवी तक, सभी 10 किलोग्राम का उपयोग कर हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी का अधिकांश उपयोग हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी में करता है। इन ड्रोनों का उपयोग पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों, जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, कर रहे हैं, जो छोटे हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री को भारतीय सीमा पर गिरा देते हैं। इसके अलावा, ये ड्रोन पंजाब जैसे राज्यों में हेरोइन और अन्य मादक पदार्थों की खेप ला रहे हैं, जो नशे की लत को बढ़ावा देते हैं और युवाओं को बर्बाद करते हैं।

भारतीय सेना ने ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई है, जो शुरुआती चेतवानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर्स और ड्रोन को प्रत्यक्ष रूप से गिराने की तकनीक शामिल है। सेना अब लो-लेवल लाइटवेट रडार तैनात करती है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन को पहचान सकते हैं। ये रडार डॉपलर तकनीक का उपयोग करके ड्रोन को पक्षियों से अलग कर सकते हैं। अब ड्रोन की उड़ान के पैटर्न को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खतरों को पहचान सकते हैं। ड्रोन को मार गिराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। पुरानी तकनीक से कुछ ड्रोन को रोक पाना मुश्किल है। ऐसे में, भारतीय सेना ड्रोन-ऑन-ड्रोन युद्ध तकनीक बना रही है, जो ड्रोन-ऑन-ड्रोन युद्ध में दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार सकती है। इसके अलावा, ट्रक-माउंटेड एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सेना में शामिल किए जा रहे हैं, जो कई ड्रोन को एक साथ मार गिराने की क्षमता रखते हैं। जिससे न केवल सीमा पर बल्कि देश में भी कहीं अगर

कोई सुरक्षा व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से सेंध लगाना चाहे तो इस तरह के प्रयासों को पूर्णतया नष्ट किया जा सके। चीन की भूमिका इस ड्रोन युद्ध में पाकिस्तान को मदद देती है और उसके इस मंसूबे के लिए महत्वपूर्ण है। ज्यादातर ड्रोन या तो चीन में बनाए गए हैं या फिर उनमें चीनी पुर्जे लगे हैं। चीन का ड्रोन उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है और उसकी तकनीक गैर-सरकारी संस्थाओं तक पहुंच रही है। पाकिस्तान को भी चीन से ड्रोन तकनीक और प्रशिक्षण मिलने की खबरें आती हैं। ऐसे में पाकिस्तान के भविष्य में घातक ड्रोन का उपयोग करने की आशंका बढ़ जाती है। भारत ने रक्षात्मक और साथ ही साथ आक्रामक ड्रोन युद्ध नीति भी विकसित की है। डीआरडीओ एक स्वदेशी ड्रोन स्वाम बना रहा है जो कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में सक्षम होगा। भारत भी अपने स्वदेशी सैन्य ड्रोन, जैसे रस्तम-2 और आर्कर बना रहा है, जिन्हें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। इसके अलावा, भारत मार गिराने की क्षमता रखते हैं। जिससे न केवल सीमा पर बल्कि देश में भी कहीं अगर

निगरानी तंत्र बना रहा है। इन साझेदारियों से भारत ड्रोन युद्ध में तकनीकी क्षमता हासिल करेगा।

भारत को तकनीक के अलावा मजबूत कानूनी ढांचे की भी जरूरत है। राष्ट्रीय एजेंसी निगरानी नेटवर्क को सैन्य और नागरिक डेटाबेस से जोड़कर किसी भी गैरकानूनी ड्रोन गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सकेगा। ड्रोन तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए आतंकवाद निरोधक कानूनों को सख्त बनाना आवश्यक है। साथ ही, पाकिस्तान और उसके समर्थकों की साजिशों को विफल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। ड्रोन युद्ध अब भविष्य का सपना नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। भारतीय सेना की सक्रियता और उसके प्रौद्योगिकी का विकास इस लड़ाई में महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी रक्षा रणनीति को विकसित करते रहें और नई तकनीक को अपनाते रहें। यह लड़ाई सिर्फ भारत की सीमा की रक्षा की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और चीन से हमारे समाज और युवा लोगों को बचाने की भी है।

सरकार को राज्यों के साथ मिलकर सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रम भी शुरू करने की जरूरत है, इससे स्थानीय लोग सुरक्षा एजेंसियों को संधिध ड्रोन की जानकारी दे सकेंगे। यही कारण है कि सीमा सुरक्षा बलों (ब्रह्म) को अधिक बल और संसाधन मिलने की जरूरत है, ताकि वे ड्रोन की तस्करी पर तुरंत रोक लगा सकें। हमें ड्रोन हमलों का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी समझना होगा। हमारे नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए बार-बार सीमा पर से ड्रोन घुसपैट इससे निपटने के लिए जागरूकता अभियानों और मीडिया का सहारा लेना चाहिए, ताकि लोग सतर्क रहें और देश में भय का माहौल न फैले। अंत में, पाकिस्तान की यह नई कार्रवाई सिर्फ सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करने की एक लंबी योजना का हिस्सा है। हमें सरकार, सेना और आम जनता को इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करना होगा। नई युद्धनीति में सूचनाओं का सही उपयोग और त्वरित कार्रवाई भी महत्वपूर्ण होंगे।

आप की बात

बसपा में उठापटक

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा नेता मायावती ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर ताबड़तोड़ फैसले लेकर पार्टी समर्थकों एवं राजनीति में बसपा में मची उठापटक को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अपने उत्तराधिकारी की भूमिका से हटाने के बाद उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी-बसपा में कभी मजबूत स्तंभ रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण मायावती ने पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह सब घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल

रहा है और लगातार असफलताओं के कारण पार्टी में विश्वास की भारी कमी पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा में मची उठापटक को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अपने उत्तराधिकारी की भूमिका से हटाने के बाद उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी-बसपा में कभी मजबूत स्तंभ रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को अनुशासनहीनता के कारण मायावती ने पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यह सब घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बसपा में सब कुछ ठीक नहीं चल

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

एमएसएमई का महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय उद्योगों को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपति अनुसंधान करके नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और अधिक कारगर बनाकर उसका उपयोग सभी उद्योगों में आधुनिक तकनीक बनाने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अनेक चीजों को विदेश से आयात करना पड़ रहा है, जबकि भारत के प्रतिभाशाली युवा ही इन चीजों को विदेश में जाकर बना रहे हैं। सरकार ने एमएसएमई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। त्रुष्टा वितरण के नए तरीके विकसित करने से एमएसएमई को कम लागत और समय पर त्रुष्टा मिल सकेगा। देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के पांच लाख उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का त्रुष्टा देने की योजना है। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को विस्तारित किया है। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं। इससे एमएसएमई का महत्व वृद्ध होना है जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहे हैं।

- मधु सुभाष बुद्धवन वाला, रतलाम

जेलेंस्की की जिद

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में संयम और दूरदृष्टि की कमी है तभी दुनिया के प्रमुख देशों द्वारा समझाने के बावजूद तीन साल से चल रहा रूस से युद्ध थम नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं शांति है का मंत्र यूक्रेन और रूस दोनों को दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जेलेंस्की को व्हाइट हाउस इसलिए बुलाया था कि यूक्रेन-रूस के बीच युद्धविराम करा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी चर्चा कर ली थी। बावजूद इसके जेलेंस्की की नासमझी कर्हें या वैचारिक अपरिपक्वता उन्होंने तीखे स्वर में चर्चा करके अमेरिका यात्रा को निरर्थक बना

दिया। यूरोप से भी उनको कोई विशेष राहत नहीं मिली। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्थिक और रक्षात्मक सुविधाओं को रोकना ही शुरू नहीं किया बल्कि रास्ते में भेजी जा रही रक्षा सामग्री भी रोक दी। यूक्रेन शांति की बात करने के बजाय उल्टे रूस पर आक्रामक कार्रवाई करने में भी नहीं चूक रहा है। ये सब उसकी नासमझी की ओर ही इशारा कर रहा है। जेलेंस्की की जिद अब न केवल यूक्रेन, बल्कि सारी दुनिया के लिए खतरा बन गई है। ऐसे में यूक्रेन की जनता को उनके स्थान पर कोई ऐसा नेता बनाना चाहिए जो विश्व जनमत का सम्मान करते हुए शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ते हुए व्यापक सहमति बनाने का प्रयास करें।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

अभिव्यक्ति की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आप रैट्टस का अपमान कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो इस तरह कार्यक्रम में उगल दिया है। अदालत को ऐसे व्यक्ति की बात क्यो सुननी चाहिए? आप हमें बताइए कि आपने जो शब्द चुने हैं उनसे मान-पिता शर्मिंदा होंगे, बेटियां-बहनें शर्मिंदा होंगी, आपका छोटा भाई शर्मिंदा होगा और पूरा समाज शर्मिंदा होगा। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस भी कई बार अभिव्यक्ति की आजादी का मर्म नहीं समझ पाती है और छोटी-मोटी टिप्पणी करने

वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों व संविधान में वर्णित उनके कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने की ओर भी संकेत किया है। प्राचीन कहावत है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपनी छड़ी नचाने की स्वतंत्रता है, बशर्त कि उससे किसी दूसरे की नाक पर प्रहार न हो। इलाहाबादिया जैसे विदेशों से अंधी नकल करने वाले लोगों को भारतीय समाज व महिलाओं की संवेदनशीलता पर खासतौर से गौर करना चाहिए।

- विभूति बुधव्या, खाकरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

हिंदूवादी संगठनों ने शांति समिति की बैठकों को बताया मात्र औपचारिकता

संवाददाता। जालौन, उर्ई

हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चौकी व कोतवाली स्तर पर आयोजित होने वाली शांति समिति की बैठकों को औपचारिकता में निपटाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष अनूप दीक्षित, निशांत गुप्ता, सत्यम यज्ञिक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुष्पेंद्र सिंह, रोहित बाथम आदि ने एसडीएम विनय मौर्य को शिकायती पत्र देकर बताया कि विभिन्न त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण समारोहों पर चौकी और कोतवाली स्तर पर शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों के माध्यम से नगर एवं क्षेत्र के संत्रांत नागरिकों, विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य



वार्तालाप के माध्यम से संभावित समस्याओं और उनके समाधान पर विचार विमर्श होता है। साथ ही सरकार की मंशा को जनता तक पहुंचाने का भी अहम माध्यम यह बैठकें हैं। क्योंकि विभिन्न स्तर के अधिकारी सीधे जनता से रूबरू होते हैं। इन बैठकों से जहां सामाजिक सौहार्द कायम करने में बल मिलता है तो वहीं, नगर एवं क्षेत्र की समस्याओं से भी अधिकारी रूबरू होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते करीब छह माह से ऐसी बैठकों को औपचारिक बैठक बना दिया गया है। इन बैठकों में

शामिल होने के लिए गिने चुने लोगों को सूचना ही नहीं दी जाती है। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मात्र औपचारिकता निभाने आते हैं। जो समस्याएं इन बैठकों में आती हैं उनके निराकरण से इनका कोई सरोकार नहीं रहता है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों की सूचना विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों को भी दी जाए। साथ ही बैठकों में जो समस्याएं आती हैं उनका समयबद्ध तरीके निस्तारण कराया जाए।

प्रदेश स्तरीय बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

अमेठी। जिला खेल कार्यालय के उपक्रीडाधिकारी शमीम अहमद ने बताया कि खेल निदेशालय के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में आवासीय क्रीडा छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रदेश स्तरीय 15 वर्ष से कम आयु के बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आज जनपद के डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्र ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा किया। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन कबड्डी प्रतियोगिता दो टीमों (टीम-ए तथा टीम-बी) के मध्य खेला गया, जिसमें वाराणसी ने 44-17 से लखनऊ, आगरा ने 33-03 से सहारनपुर व गोरखपुर ने 28-21 से मेरठ एवं अयोध्या ने 20-07 से आजमगढ़ तथा वाराणसी ने 17-15 से गोरखपुर को

हराया। इस क्रम में उन्होंने बताया कि आवासीय क्रीडा छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रदेश स्तरीय कबड्डी खिलाड़ियों का (फिजिकल टेस्ट एवं रिस्कल टेस्ट तथा डॉक्टरों द्वारा मेडिकल जांच) भी हुई एवं इस अवसर पर कबड्डी संघ के आबजर्वर रामपाल उपस्थित रहे तथा उपक्रीडाधिकारी शमीम अहमद ने आये हुए अतिथियों का स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन में निर्णायक के रूप में जय प्रकाश यादव, रोहित ठाकुर, गोपी यादव, सत्य प्रकाश राजभर, राजेन्द्र पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया तथा उक्त दो दिवसीय प्रतियोगिता का फाइनल मैच 06 मार्च को खेला जायेगा। इस दौरान प्रतियोगिता में खेल विभाग अमेठी के कनिष्ठ सहायक शिवकुमार मौर्य एवं प्रशिक्षक नदीम, मी0 आरिफ, लबली तिवारी, मोना सिन्हा ने उपस्थित रहकर प्रतियोगिता के आयोजन में अमूल्य योगदान दिया।

एनएसएस सेवकों ने भुजैनी स्कूल पर चलाया स्वच्छता अभियान

संवाददाता। संतकबीरनगर



गंगा देवी कपिलदेव तिवारी पीजीकॉलेज भुजैनी, संत कबीर नगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सप्त दिवसीय विशेष शिविर का का शुभारंभ किया गया। विशेष शिविर के लिए ग्राम सभा भुजैनी के प्राथमिक विद्यालय का चयन किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0संतोष कुमार सिंह ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अलावा सामुदायिक सेवा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिविधियों का एक विस्तार है जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक को एक शैक्षणिक वर्ष में

120 घंटे की सामाजिक सेवा पूरी करनी होती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 रंगनाथ तिवारी ने सप्त दिवसीय विशेष शिविर के शुभारंभ के अवसर पर स्वयंसेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से स्वयंसेवियों को समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य है। सप्त दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को

विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महाविद्यालय के मुख्य निर्यंत्रण हरिशंकर जी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्वयंसेवकों को विद्यार्थी जीवन से ही समाज उपयोगी कार्यों में रत रहने एवं उनमें समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। भोजनीपराल द्वितीय सत्र में स्वयंसेवियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें विभिन्न प्रकार के स्लोगन तारों पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए ग्राम सभा भुजैनी में साफसफाई की गई।

एचआरपीजी कालेज में रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन



संतकबीरनगर। सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, हीरालाल रामनिवास पीजी कॉलेज खलीलाबाद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सप्ताह का प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रथम दिवस का सफल शुभारंभ बुधवार को रंगोली प्रतियोगिता से हुआ। रंगोली प्रतियोगिता में कुल आठ समूह में छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्राओं में रीमा, अंजु, रूबी, महक, शाहिदा, सलोनी, मनोरमा, अर्चना इत्यादि उपस्थित रही। रंगोली प्रतियोगिता प्रभारी डॉ0 संध्या राय, सहप्रभारी डॉ0

आशा मिश्रा तथा सदस्य डॉ0 शिल्पी सिंह, श्रीमती कंचन लता पांडेय, सुश्री प्रेमलता, सुश्री शोएबा के नेतृत्व में बच्चों ने कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। रंगोली का मूल्यांकन निर्णायक मंडल में प्रो0 दिनेश गुप्त, डॉ0 नेहा सिंह, डॉ0 अनुभव श्रीवास्तव द्वारा रंगोली की थीम 'सेवा वादर सेवा लाइफ' विषय पर प्रतिभागियों से प्रश्न करते हुए मूल्यांकन किया गया। छात्राओं ने विभिन्न रंगोलियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में जल के महत्व का संदेश देने का सफल प्रयास किया।

सदर विधायक अनिल प्रधान ने विधानसभा ने जर्जर सम्पर्क मार्गों का मुद्दा

संवाददाता। चित्रकूट

विधानसभा में बुधवार को सदर विधायक अनिल प्रधान ने विधानसभा में नियम-51 के अन्तर्गत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जनपद चित्रकूट के विधानसभा क्षेत्र-236 अन्तर्गत ग्राम पंचायत संग्रामपुर में बाबूलाल चौराहा-खोही शिवरामपुर मार्ग से सेट की बगिया तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत भदेंदू में प्राथमिक विद्यालय खोंपा से यमुना नदी के किनारे तक जर्जर सम्पर्क मार्ग के निर्माण आदि के जनहित से जुड़े मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।



वर्षों के खूब खर्च के बाद भी जर्जर रहने के कारण जगह-जगह जलभराव बने रहने से ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। साथ ही आवागमन पूरी तरह बाधित रहता है। बच्चों को स्कूल आने-जाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए उक्त ग्राम पंचायतों में शूच्य से लेकर लेपन तक सड़क का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। साथ ही सदर विधायक ने जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कवी अन्तर्गत ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में 33/11 के वी0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का मुद्दा उठाया। विधायक ने इस क्षेत्र के लोगों की विद्युत समस्या अत्यंत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र में अधिक लोड होने के कारण अद्वतन लो-वोल्टेज रहने के चलते क्षेत्रीय जनता व किसान भाइयों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि विद्युत व्यवस्था ठीक न होने के चलते इस क्षेत्र के दर्जनों गांव इस समस्या से बाधित हैं।

बरद्वारा माईनर नहर तक सम्पर्क लम्बाई, ग्राम पंचायत लोहदा गांव से औदहा तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत मरसी बुजुरी में मुख्य सम्पर्क मार्ग से राजबहादुर कोरी के घर तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत कलवाखुर्द में अहिरन पुरवा बदी के डेरा से खेरिया तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत नहरा मजरा आगरहाड़ा से बरूआ बांध नहर तक का सम्पर्क मार्ग, ग्राम पंचायत ब्यौड़ा प्राथमिक विद्यालय से लोहन पुरवा भानपुर तक सम्पर्क मार्ग आदि पूरी तरह से ध्वस्त होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता

पिटाई से युवक की मौत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज

लालगंज, रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र के पूरे अजबी मजरे ऐहार गांव में मारपीट के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पीएम के लिये भेज दिया है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिये छापेमारी कर रही है। पूरे अजबी गांव निवासी अमित पाल ने पुलिस को दिये गये शिकायती पत्र में बताया कि बीती सायं गांव के ही प्रदीप पासवान व अजीत वर्मा ने पुरानी कहासुनी को लेकर उनके चाचा सर्वेश पर हमला बोल दिया। चाचा को बचाने में उसके साथ रतीपाल को भी आरोपियों ने लाठी डंडी, कुल्हाड़ी व पिसासों से हमला कर दिया। जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से जखमी हो गये। आनन-फ़ानन तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी प्रदीप व अजीत के खिलाफ मामला पंजीकृत कर दिया है।

पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

श्रावस्ती। विदित है कि महत्वपूर्ण व चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा स्वयं महत्वपूर्ण और चिन्हित अभियोगों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है और निरंतर इन महत्वपूर्ण व चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोगों में त्वरित निस्तारण व अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारी व परोकारों को निर्देशित भी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में विशेष लोक अभियोजक संयुक्त निदेशक अभियोजन मॉनिटरिंग सेल शासकीय अधीक्षक तथा कोर्ट परोकार मोहरीर के प्रयास एवं की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज बुधवार को न्यायालय पॉक्सो जनपद श्रावस्ती ने थाना हरदत्तनगर गिरफ्त पर पंजीकृत

मु0अ0सं0 249/2024 धारा 64(2)स्र 65(2) 352 351(3) बीएनएस व 5(डू)/6 पॉक्सो एक्ट बनाम श्रयण कुमार उर्फ गोकुल पुत्र बेचुराम निवासी थाना क्षेत्र हरदत्तनगर गिरफ्त जनपद श्रावस्ती के वादिनी की 05 वर्षीय बच्ची के साथ उसके सगे चाचा द्वारा दुष्कर्म करने गाली व जान से मारने की धमकी देने के अपराध में मात्र 50 दिवस में आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना हरदत्तनगर गिरफ्त पर 27 दिसंबर 2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना नियत समय पर सम्पादित कर न्यायालय प्रेषित की गयी थी। मिशन शक्ति के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए महिला संबंधी अपराधों में प्राथमिकता देते हुए 05 वर्षीय बच्ची के साथ पैरवी के फलस्वरूप आज बुधवार को धमकी के अपराध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रसव पीड़ा में गंभीर स्थिति से जूझती गर्भवती का हुआ सफल ऑपरेशन

संवाददाता। माधौगढ़, जालौन

प्रसव पीड़ा से छटपटाती गर्भवती महिला का गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ में डॉक्टर पूजा राजपूत ने सफल ऑपरेशन करके स्थानीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ में डॉक्टर पूजा राजपूत (गायनोलॉजिस्ट) ने एक ऐसी गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है कि यदि थोड़ा सा भी विलंब हो जाता तो जच्चा-बच्चा के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था। मंगलवार की शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ में प्रसव पीड़ा से तड़पती ग्राम गोहनी(भंग) निवासी 24 वर्षीय एक गर्भवती महिला को लाया गया जहां उसकी हालत देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता था कि यह प्रसव



पीड़ा असामान्य है। चिकित्सालय में उपस्थित डॉक्टर पूजा राजपूत (गाइनोलॉजिस्ट) ने स्थिति को समझा और स्टॉथेस्कोप की मदद से गर्भवत्य शिशु की हार्टबीट (दिल की धड़कन) की जांच की जो 110 से 160 प्रति मिनट के सापेक्ष बहुत कम थी। जात हो कि यदि गर्भवत्य शिशु की हृदय गति सामान्य नहीं है तो बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इन परिस्थितियों में जच्चा और बच्चा का जीवन खतरनाक स्थिति से गुजरता है। महिला चिकित्सक पूजा

राजपूत ने इस स्थिति से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (अधीक्षक) डॉक्टर मनीष राजपूत एवं डॉक्टर कुलदीप राजपूत से चर्चा कर इमरजेंसी सीजर ऑपरेशन की जरूरत पर वल दिया। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर मनीष राजपूत एवं डॉ. कुलदीप राजपूत के साथ सहमति बनने पर डॉक्टर पूजा राजपूत ने गर्भवती महिला का वह ऑपरेशन किया जो मेडिकल कॉलेज या बहुत अधिक सुविधा साधन संपन्न चिकित्सालयों में ही संभव है। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप राजपूत निस्तेजक के रूप में उपस्थित रहे। ऑपरेशन की सफलता से प्रसन्न डॉक्टर पूजा राजपूत ने बताया कि बच्चा जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष राजपूत ने बताया कि इस प्रकार की सुविधा भविष्य में भी जारी रहेगी।

जिलाधिकारी ने स्ट्रॉग रुम का किया निरीक्षण



अमेठी। जिलाधिकारी निशा अनंत द्वारा तहसील गौरीगंज परिसर में स्थित ईवीएम, वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल रूम, स्ट्रॉग रूम, रिजेक्टेड यूनिट एंड, वीवी पैट कक्ष का अवलोकन किया गया। उक्त वेयर हाउस में विधानसभा क्षेत्र-अमेठी, गौरीगंज, तिलोई व जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम, वीवीपैट मशीनें लॉक के अन्दर संरक्षित हैं। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रॉग रूम की सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाय। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि/रा अर्पित गुप्ता, मांगला प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व जिला निर्वाचन कार्यालय के स्टफफोन उपस्थित रहे।

अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत



महराजगंज, रायबरेली। महाराजगंज रायबरेली रोड पर गैस ऐजेंसी के नजदीक छोटे भाई को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रहे बाइक सवार युवक को तेज रफतार अनियंत्रित पिकअप ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सीपेडसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार की देर रात की है, कोतवाली क्षेत्र के गांव बसकाट निवासी मनीष शुक्ला (35) पुत्र जगत नारायण शुक्ल अपने छोटे भाई

पेंशनरों ने लिपिक पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, सौपा ज्ञापन



उर्ई, जालौन। पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का समय से परीक्षण नहीं किए जाने तथा उनके बिल भुगतान को भी समय से कोषागार में संप्रेषित न किए जाने का चकबंदी विभाग के लिपिक पर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता मंत्री राधाधरम गोस्वामी अखिलेश खरे गया प्रसाद प्रजापति वीरेंद्र केश कुमार आदि ने जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे को एक शिकायती पत्र देते हुए चकबंदी विभाग के लिपिक पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस विभाग में तैनात क्षमा द्वारा पेंशनर्स को परेशान किया जाता है उनके द्वारा सरकार की योजनाओं का पेंशनर्स को समय से लाभ नहीं मिल पा रहा है। उक्त लिपिक द्वारा पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर ना तो कार्रवाई की जाती है और ना ही उनका समय से परीक्षण किया जाता है, इतना ही नहीं उनके द्वारा बिलों को भी कोषागार में समय से संप्रेषित नहीं किया जाता है, जिससे पेंशनर्स को परेशान होना पड़ रहा है उन्हें समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा है।

सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक दूजे का हाथ थाम 11 जोड़े बंधे वैवाहिक बंधन में

संवाददाता। कुसमिलिया, जालौन

डकोर गांव में स्थित बजरंग सत्संग आश्रम में प्रति वर्ष के भाति राधे सेवार्थ द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में दलित समाज के 11 जोड़ों को हिन्दू रीति-रिवाजों से विवाह के पवित्र बंधन में बांधा गया। आयोजकों ने वर-वधुओं को उपहार भेंट कर आशीर्वाद दिया। डकोर गांव में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंगलवार की शाम हिंदू रीति रिवाज से कसबे में दलित समाज के दूल्हों की बारात घूमि जिसमें दलित समाज के दूल्हे घोड़ी पर सवार हुए। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कई महिलाओं ने दरवाजे पर तिलक कर पुष्पों की बारिश की। बँड-बाजों के साथ दूल्हों की बारात बजरंग सत्संग आश्रम पहुंची। जहां वधु पक्ष कार्यक्रम संयोजक ज्ञान सिंह यादव, मनीष यादव, विनोद यादव ने उनका तिलक किया और भेंट दी। भेंट में



ग्यारह सौ रुपए की दक्षिणा हर घोड़े को दी। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें 11 वर-वधुओं ने एक-दूसरे को जीवन साथी चुनते हुए बरमाला पहनाई और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। आयोजकों ने भी नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर गृहस्थी में उपयोगी सामान उपहार स्वरूप भेंट कर उनके वैवाहिक जीवन की मंगलकामनाएं की। वही मुख्य अतिथि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव ने वर-वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा बुदेलखंड की तस्वीर बदलने के

लिए गांव के समाजसेवियों द्वारा यह अच्छी पहल की गई। जिसमें सामूहिक विवाह में दलित समाज की लड़कियों के दूल्हे घोड़ी पर चढ़कर आए। जिससे समाज को नई दिशा मिली। समाज में ऐसे कार्यों से बहुत ही पुण्य मिलता है। ऐसे कार्य आयोजकों द्वारा बरबर होना चाहिए। वही फग सम्राट राजेंद्र गुर्जर व बुजेंद्र गुर्जर द्वारा बुदेलखंडी लोकगीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर पूर्व ब्लाक आयोजकों द्वारा बरबर होना चाहिए। लोकिन मामले की जानकारी आम लोगों को हुई तो वह खफ हो गये और अध्यक्ष सञ्जन त्रिपाठी, रामकुमार तिवारी, विवेक कुमार, पवनदीप निषाद प्रभान सहित आधा सैकड़ लोग शामिल रहे।

अनर्गल आरोपों से भड़के सर्वजन समाज के लोगों ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन



कालपी, जालौन। गत समाधान दिवस में अभा ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पर अनर्गल आरोप लगाए जाने से लोग खफा हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में तहसील पहुंचे सर्वजन समाज ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। विदित हो कि गत 1 मार्च को तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस के दौरान रिटायर्ड दरोगा तथा सपा नेता ने अभा ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष राजू पाठक पर कई आरोप लगाए थे। लोकिन मामले की जानकारी आम लोगों को हुई तो वह खफ हो गये और अध्यक्ष सञ्जन त्रिपाठी, रामकुमार तिवारी, विवेक कुमार, पवनदीप निषाद प्रभान सहित आधा सैकड़ लोग शामिल रहे।

अवैध अतिक्रमण कर बनायी दुकानों का पालिका तैयार करे खाका: एसडीएम

संवाददाता। कालपी, जालौन

टरननगंज में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल सकता है। उप जिलाधिकारी ने पालिका प्रशासन को निर्धारित सीमा से बाहर बनी दुकानों का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगर मामले में कोई बाधा नहीं आई तो लोगों को अंदर बाजार में जैम से निजात मिल सकती है। विदित हो कि टरननगंज बाजार में आवागमन व्यवस्था ठीक नहीं है। दुकानों के तय सीमा से बाहर आ जाने से दिनभर जैम की स्थिति बनी रहती है जबकि उक्त रोड तहसील जाने का प्रमुख मार्ग है जैसा से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वही एसडीएम ने सभी को आइडेंट किया है कि जांच कराकर दीर्घियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अभा ब्राह्मण महासभा के नगर अध्यक्ष सञ्जन त्रिपाठी, रामकुमार तिवारी, विवेक कुमार, पवनदीप निषाद प्रभान सहित आधा सैकड़ लोग शामिल रहे।

लिए उन्हें उन्हें एक किलोमीटर से अधिक का चक्र लगाया पड़ता है लेकिन इतनी समस्या होने के बाद भी यहां तय सीमा से बाहर बनी दुकानों के खिलाफ अभियान नहीं चला है जिसकी वजह से तहसील जाने वाला यह मार्ग सिक्कड़ कर गली बन गया है। ऐसा भी नहीं है कि नगर की इस समस्या से सब अनभिज्ञ हो लेकिन इस परेशानी को खिलाफकिसी ने नहीं उठाई है हालांकि एसडीएम सुशील कुमार सिंह इस समस्या के प्रति गम्भीर हैं। उन्होंने पालिका के जिम्मेदार अधिकारी को इस रोड पर फैले अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिससे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। एसडीएम की माने तो इस रोड पर ज्यादातर दुकानें नगरपालिका परिषद द्वारा बनाई गई नाली के बाहर बन गयी हैं जिससे सड़क संकरी हो गई है लेकिन अब नगर के अन्य स्थानों के साथ इस रोड पर भी अतिक्रमण के शीघ्र खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

दलित से मारपीट मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया कालपी, जालौन। दलित व्यक्ति ने विशेष वर्ग के लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। नगर के खिलाफकिसी ने नहीं उठाई है हालांकि एसडीएम सुशील कुमार सिंह इस समस्या के प्रति गम्भीर हैं। उन्होंने पालिका के जिम्मेदार अधिकारी को इस रोड पर फैले अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं जिससे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। एसडीएम की माने तो इस रोड पर ज्यादातर दुकानें नगरपालिका परिषद द्वारा बनाई गई नाली के बाहर बन गयी हैं जिससे सड़क संकरी हो गई है लेकिन अब नगर के अन्य स्थानों के साथ इस रोड पर भी अतिक्रमण के शीघ्र खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए 80 लोगों ने पेश किया दावा

प्रस्तावकों ने आठ-आठ नामांकन पत्रों में किए हस्ताक्षर

नामांकन पत्र में ही वापसी का उल्लेख

संगठनात्मक खाती के चलते कई मंडलों का प्रतिनिधित्व रहा शून्य

संवाददाता। फतेहपुर



अनू श्रीवास्तव, महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति प्रवीन व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास प्रकाश, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा, नगर पंचायत किशनपुर अध्यक्ष, जिला चुनाव सह अधिकारी उदय मोदी व मनोज मिश्र मनु आदि ने जिला चुनाव अधिकारी रितेश गुप्ता (विधायक मेरठ) व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी रंजना उपाध्यक्ष के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। जानकारी के अनुसार भाजपा के संगठनात्मक चुनावों की कड़ी में आज यहां जिलाध्यक्ष चयन को लेकर पार्टी कार्यालय में जिला चुनाव अधिकारी रितेश गुप्ता द्वारा आवेदन पत्र लिये गये। इस मौके पर

जिला अध्यक्षी के लिए मौजूदा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी व आशीष मिश्रा के साथ-साथ पूर्व व मौजूदा जिला पदाधिकारियों द्वारा आवेदन किए गए हैं। जिले के 23 मंडलों में सबसे अधिक नगर उत्तरी मंडल के 20 भाजपाइयों ने, वहीं नगर दक्षिणी के 17 कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन पत्र जमा किए गए। इसके अतिरिक्त नगर उत्तरी के दंपति पं. पंकज त्रिपाठी व उनकी पत्नी अंजू त्रिपाठी द्वारा किया गया। पार्टी के एक अन्य नेता दंपति द्वय अवधेश मिश्रा और उनकी पत्नी रेखा मिश्रा, ससुर-दामाद ओम मिश्रा

(जिला पंचायत सदस्य) व मनोज मिश्र मनु (जिला चुनाव सह अधिकारी) के भी आवेदन पार्टी गलियारे में खासा चर्चा का विषय रहे। इसके साथ-साथ किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय प्रताप व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ज्योति प्रवीण, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने भी आवेदन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए आज हुए नामांकनों में ज्यादातर नामांकन पत्रों में ऐसे प्रस्तावक शामिल रहे, जिन्होंने कई कई के पत्रों में हस्ताक्षर किए थे। नियमानुसार मण्डल अध्यक्ष/जिला प्रतिनिधि ही इसके लिए नामांकन पत्र में हस्ताक्षर कर सकते हैं। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले सिर्फ एक पत्र में ही हस्ताक्षर की व्यवस्था समाप्त किए जाने से इतनी बड़ी संख्या (81) में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर हो पाए। नियमों में परिवर्तन न होता तो अधिकतम चौदह नामांकन पत्र ही दाखिल हो पाते। ऐसे में जिले के संगठनात्मक ढांचे को लेकर तरह तरह के सवाल उठते और बड़ी

फर्जीहट होती, संभवतः इससे बचने के लिए नियमों में परिवर्तन हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए आज यहां बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने नामांकन कराया। नामांकन पत्र में सबसे नीचे पचास वापसी का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें (बगैर भ्रू) सभी से हस्ताक्षर कराए गए। बताया गया कि भविष्य में जब भी किसी एक के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा तो कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा बताया गया। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का जिले में संगठनात्मक समेत कई मंडलों में पहले तो गठन नहीं हो पाया, जिससे जिला संगठन के चुनाव संचालन में गड़बड़ें बढे बढते में पड़ने की संभावनाएं बलवती हो गई थीं किंतु आनन फानन में दो दिन पूर्व तीन मण्डल अध्यक्षों की घोषणा करवाकर जिला संगठन ने अपनी फजीहत तो बचा ली किन्तु अभी कई ऐसे मंडल रह गए हैं।

सीएसआर से रौशन हुआ आयुष्मान आरोग्य मंदिर भानपुर, डीएम ने किया लोकार्पण

आठ सब सेंटों को मिली उपयोगी सामग्री की सौगात

संवाददाता। लखीमपुर खीरी



डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आवाहन पर बलरामपुर फाउंडेशन ने सीएसआर फंड से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ का 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर भानपुर' नवीनीकरण और सौन्दर्यकरण कार्य से रौशन हुआ। जिसका लोकार्पण डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बलरामपुर फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक अर्वातिका सरावगी, सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक योगेश कुमार सिंह संग लोकार्पित कर जनमानस की सेवा को समर्पित किया। इस मौके पर पांच महिलाओं को पिंक हेल्मेट का विवरण भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते

हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि आशा बहनों की समाज में भूमिका अहम है, यह महिलाओं और बालिकाओं को स्वस्थ खानपान की सलाह देकर एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाती है। महिलों और बालिकाएं उनको सलाह पर अमल करती हैं। बलरामपुर फाउंडेशन ने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च सामाजिक कल्याण को बखूबी निभाया है। इस केन्द्र को हमेशा चकाचक बनाए रखें। इसकी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। डीएम ने कहा कि बलरामपुर फाउंडेशन ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर भानपुर के नवीनीकरण और

सौन्दर्यकरण कार्य कराने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के आठ स्वास्थ्य उपकेंद्रों किए 08 सेट इनवर्टर और बालिकाओं को स्वस्थ खानपान की सलाह देकर एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाती है। महिलों और बालिकाएं उनको सलाह पर अमल करती हैं। बलरामपुर फाउंडेशन ने क्षेत्र के विकास के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि खर्च सामाजिक कल्याण को बखूबी निभाया है। इस केन्द्र को हमेशा चकाचक बनाए रखें। इसकी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है। डीएम ने कहा कि बलरामपुर फाउंडेशन ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर भानपुर के नवीनीकरण और

लेवी में जमा नौ लाख रुपए से आयुर्वेद अस्पतालों में होगी वस्तुओं की खरीद

संवाददाता। हमीरपुर

आयुर्वेद अस्पतालों में मरीजों के पर्च यानी लेवी से जमा होने वाले पैसे से अब आयुर्वेद अस्पतालों का विकास किया जायेगा। प्रंद्रह साल बाद शासन ने यह व्यवस्था फिर से शुरू की है। जिले में नौ लाख से अधिक की धनराशि लेवी की जमा हो चुकी है। आयुर्वेद यूनानी अधिकारी ने जिले के सभी अस्पतालों से मांग पत्र मंगा लिये हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में आयुर्वेद के 22 व दो यूनानी अस्पताल स्थापित हैं। हालांकि जिले में इन अस्पतालों का हालत बेहद खराब है, अस्पताल से एक रुपये का मरीजों को पर्चों काटा जाता है जिससे अब तक रोगी कल्याण समिति में करिव नौ लाख रुपये जिले में जमा हो चुका है प्रंद्रह साल पहले लेवी के धन से कुछ सामान अस्पताल के लिये खरीद लिया जाता था मगर प्रंद्रह साल से यह व्यवस्था समाप्त हो गयी थी। हालांकि प्रदेश में जमा लाखों रुपये पर आइटि में लेखा परीक्षक ने आपत्ति उठायी थी जिस पर शासन ने कहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुसार सभी अस्पतालों से मांग के आधार पर सामान खरीद लिया जाये। जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी एनबी सिंह का कहना है कि अस्पतालों से मांग पत्र मंगा लिया गया है, जैम पोर्टल से सामान की खरीदारी की जायेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर लिया गया है। उसी के आधार पर अस्पतालों का सामान

डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति से लेवी खरीदारी, अस्पतालों से मांगे गये मांग पत्र

खरीदा जायेगा, इसमें कुर्सी मेज व अन्य सामान अस्पतालों में पहुंच जायेगा जिससे व्यवस्थाएं कुछ ठीक हो जायेगी। आयुर्वेद दवाओं के फेल सैम्पल को बचो छिपा रहे हैं यूनानी अधिकारी हमीरपुर। आयुर्वेद में भी दवाएं मानक के अनुरूप निर्मित नहीं हो रही हैं, पांच महीने पहले आयुर्वेद दवाओं के भंगे गये सैम्पल फेल पाये गये हैं जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है हालांकि जिला आयुर्वेद यूनानी अधिकारी एनबी सिंह फेल सैम्पल को कई महीनों से छिपाये हुये हैं, जिससे यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि आयुर्वेद की कौन दवा बाजार में नकली बिक रही है। यही नहीं जिले में संचालित आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर संचालक मनमानी दाम पर दवाओं की बिक्री कर रहे हैं मगर आयुर्वेद यूनानी अधिकारी ने इस मामले में जांच नहीं की है उनका कहना है कि वह सब अपने अनुसार काम करते हैं किसी को हमारे काम में कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, जब कि एडीएम वित्त का कहना है कि इस मामले में वह आयुर्वेद यूनानी अधिकारी से बात कर फेल सैम्पल की बात करेगें।

मिनी सेंटर आफ एक्सिलेस फॉर वेंजीटैबल इकाई का उदघाटन

फतेहपुर। जिला उद्यान अधिकारी डा. रमेश पाठक ने जानकारी दिया कि सच्चिन्धों की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। राजकीय अलंकृत उद्यान कम्पनी बाग व राजकीय औद्योगिक प्रखेत्र/पौधशाला रमवा परिसर में मिनी सेंटर ऑफ एक्सिलेस फॉर वेंजीटैबल इकाई संचालित है। किसान बीज देकर सब्जों की एक रूपरेखा प्रति पौध तैयार करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण करना होगा। उन्होंने बताया कि दोनों केन्द्र में तैयार विभिन्न प्रकार की सब्जियों की अंग्रेठी पौध सस्ती दर पर किसानों को दी जाएगी जिससे किसान अंग्रेठी सब्जियों की खेती कर उसे अच्छे भाव पर बाजार में बेंच सकेंगे। बीज देकर एक रूपरेखा प्रति पौध तैयार करा सकते हैं। यदि किसानों को केन्द्र से ही सब्जियों की पौध खरीदनी है तो उसके लिए उन्हें दो रूपरेखा प्रति पौध चुकाने होंगे। इसमें 15 से 20 दिनों के अन्दर सब्जियों की पौध तैयार हो जाती है। इन केन्द्रों में गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, करेला, खीरा सहित अन्य सब्जियों की पौध तैयार की जाती हैं। मिनी सेंटर आफ एक्सिलेस लेस में सब्जियों की पौध मिट्टी की बजाय कोकोपिट में तैयार होंगे।

गैंगस्टर का दो मजिला मकान जमींदोज स्ट्रेस रिलीफसेल ने लगाया



फतेहपुर। गैंगस्टर एक्ट से संबंधित शांति गौकश के प्रंद्रह लाख रुपए कीमत से बने दो मजिला मकान को धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए जेसीबी से जमींदोज करवा दिया गया। यह मकान कन्निरातन की भूमि पर निर्मित था। पुलिस कार्रवाई से अन्य अभियुक्तों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हथगाम थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से संबंधित शांति अभियुक्त इमरान पुत्र नसीम निवासी रायपुर मुआरी का हथगाम की प्रंद्रह लाख रुपए की अवच संपति खानिस्तान की भूमि पर निर्मित दो मजिला मकान को धारा 67 उप राजस्व संहिता के तहत बुल्डोजर से जमींदोज करवा दिया गया है। एस्पपी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ हथगाम थाने में एक दर्जन से सभ्यकार्यें साधा की एवं चिकित्सकीय परामर्श की अभियुक्तों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

स्ट्रेस रिलीफसेल ने लगाया महाविद्यालय में शिविर फतेहपुर। डॉ. भीमराव अंबेडकर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को स्ट्रेस रिलीफ सेल के तत्वाधान में छात्राओं में मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. गुलशन सक्सेना ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मनोवैज्ञानिक डॉ रिंकी लाकरा रहीं। स्ट्रेस रिलीफसेल प्रभारी डॉ बसंत कुमार मौर्य ने मंच का संचालन करते हुए कैंप के उद्देश्य पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्य गुलशन सक्सेना ने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए छात्राओं से इस कैंप का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया और आभारपत्र दिया कि यदि आवश्यकता हुई तो इस प्रकार के शिविर का पुनः आयोजन किया जायेगा। शिविर की सार्थकता व महत्व को बताते हुए छात्राओं से कहा कि बिना धरणाए और हिचकिचाहट के अपनी समस्याएं डॉ. रिंकी लाकरा से साझा करके सलाह लें। छात्राओं ने भी इस परामर्श शिविर में हिस्सा लिया और डॉ. रिंकी लाकरा से अपनी तमाम समस्याएं साझा की एवं चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। इस अवसर पर स्ट्रेस रिलीफसेल की सभी सदस्य उपस्थित रहे।

सकुशल सम्पन्न कराए नीट यूजी परीक्षा: डीएम



फतेहपुर। नीट यूजी की परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि शासनानुसार नीट यूजी की परीक्षा को सकुशल, पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों का चयन करने के लिए प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय मधुपुरी जिला विद्यालय निरीक्षक आएस में समन्वय बनाते हुए परीक्षा केन्द्रों का चयन करें और उनकी स्थलीय जांच भी करें कि सभी मानक पूर्ण करते हो। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस विभाग भी अपनी रिपोर्ट से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि शासन के आदेशानुसार जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया जाये। परीक्षा को सकुशल सफल कराने के दृष्टिगत संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य आवासक अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्या केन्द्रीय विद्यालय मधुपुरी, प्रधानाचार्या आईटीआई सहित संबधित उपस्थित रहे।

एसपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा



कानपुर देहात। पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, समस्त क्षेत्राधिकारी गण तथा समस्त थाना प्रभारी/शाखा/इकाई प्रभारी गोष्ठी में शामिल हुए तथा गोष्ठी में भा.द.वि./बीएनएस के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने पर प्राप्त प्रत्येक

छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लिया जाये तथा उसका उसी स्तर पर तत्काल एवं यथोचित निराकरण किया जाये। महिला सम्बन्धी अपराधों का तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय बरामदगी हेतु शेष अपहृत/अपहृता/ गुमशुदा की बरामदगी की समीक्षा की गई। थानों पर लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण, वांछित अभियुक्तों, पुरस्कार घोषित अपराधियों, वारंटियों को गिरफ्तारी, सिकायती प्रार्थना पत्र के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये। अनावरण हेतु शेष अभियोगों तथा पूर्व की लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने की पीस कमेटी की बैठक, दिये निर्देश

संवाददाता। कानपुर देहात

आगामी त्योहारों/पर्वों को शान्तिपूर्ण, सकुशल सम्पन्न करायें जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी आलोक्ष सिंह की अध्यक्षता में शान्ति समिति/पीस कमेटी की बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि तहसील, थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की जा चुकी है। बैठक के दौरान मल्लि शांति/समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने सभी एसडीएम व क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों के संवेदनशील स्थलों का लगातार भ्रमण करें तथा वहां से सम्बन्धित सुझाव, शिकायतों का संज्ञान लेकर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दृष्टिगत रोस्टर के अनुरूप निवाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, पेयजल की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने



हेतु डीपीआरओ व अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी एसएसओ को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहें, किसी भी अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्यवाही करें। भीड़/भाड़ वाले स्थलों पर सदाी वार्दी में महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाये, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाये, यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने सभी धर्मगुरुओं/सम्प्रान्त नागरिकों से अपील की, कि वे अपने-अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करें, कि वे किसी ऐसी गतिविधि शामिल

न हो, जो आपत्तजनक हो। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व एसएसओ को निर्देशित किया कि शनिवार तक एक बार पुनः थाना व तहसील स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की जाये, बैठक में यदि कोई समस्या/शिकायत संज्ञान में आये तो तत्काल निस्तारण करायें। उन्होंने अनिश्चान अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी थानों में अनिश्चान यंत्रों की पूरी तैयारी के साथ तैनात रखें, जिससे किसी भी घटना का तत्काल निर्यंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पर्वों के दृष्टिगत एम्बुलेंस, डॉक्टर की तैनाती करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा खाद्य विभाग को अभियान चलाकर खाद्य

बेहद सावधानीपूर्वक स्कैन करें वयूआर कोड

अनजान व्यक्ति को कदापि न दें अपना मोबाइल

फतेहपुर। जनपद में साइबर फ़्राइड के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने व इससे बचाने के उद्देश्य के तहत पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर फ़्राइड पुलिस थाना एवं समस्त थानों में साइबर जागरूकता संबंधी अभियान चलाया। अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य के तहत लोगों को साइबर अपराध के प्रकार व इससे बचने के उपायों के बारे जानकारी प्रदान करते हुए पंपलेट का वितरण किया। थानों में अपने क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल कालेज, बैंक, एटीएम, प्रमुख बाजार, बस अड्डे, चौराहे, प्रमुख व्यावसायिक दुकानों, गांव-कस्बे व अन्य जगहों पर पुलिस ने जाकर लोगों को समझाया। आमजनमानस में साइबर अपराधों के बारे में सही जानकारी न होने के कारण साइबर अपराधियों द्वारा उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई को ठा लिया जा रहा है। साइबर अपराधियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से

पहले लोगों का डाटा एकत्र करने के उपरान्त उन्हें बैंक कर्मी या विभिन्न कम्पनियों का कस्टमर केयर वनकर फ़ोन कर केवाईसी आदि के नाम पर उनके बैंक खाता, एटीएम नं०, सोबीवी नं०, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड आदि गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेती जाती है। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल एवं यूजर आईडी पासवर्ड शेयर न करें, चॉकई व बैंक कर्मी हो या दुकान आदि पर अन्य कोई। किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करके प्रयोग में न लायें। नगर प्रास करने हेतु उस कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डायन्यूट को देखें या केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नाभिकारक प्रयोग करें। एटीएम से पैसे निकालते समय ध्यान रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका एटीएम काई बदल न पावें एवं पैसा निकालने से पूर्व उस मशीन में स्कीमर एवं कैमरा न लगा हो चेक कर लें। अपने मोबाइल को किसी अनजान व्यक्ति को कदापि न दें।

एलएचडीसीपी में संशोधन किसानों के लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम

भाषा | नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दिया जाना किसानों के लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य, उच्च उत्पादकता और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी रोग नियंत्रण में सहायता करेगी, टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देगी, अधिक मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों को शामिल करेगी और पशुओं के लिए सस्ती दवाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, यह किसानों के लिए बेहतर पशु स्वास्थ्य, उच्च उत्पादकता और समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है।केंद्रीय



मंत्रिमंडल ने इससे पहले एलएचडीसीपी में संशोधन को मंजूरी दी। इस योजना के तीन घटक हैं - राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी), पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएचएंडडीसी) और पशु

औषधि। एलएचएंडडीसी के तीन उप-घटक हैं: गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सीएडीसीपी), मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (ईएसवीएचडी-एमवीयू)

प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़त की

नई दिल्ली।(भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को जापान के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की और कहा कि वह भारत के विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदार जापान के साथ आर्थिक सहयोग को गहरा बनाने को लेकर आशान्वित हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात के बाद मोदी ने कहा कि वह भारत में इनके विस्तार की योजना और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से उत्साहित हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, तत्पुओ यामुनागा के नेतृत्व में आज जापानी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत में उनकी विस्तार योजनाओं और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदार जापान के साथ आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ बनाने को लेकर आशान्वित हैं।

और पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी) एक बयान में कहा गया कि एलएचडीसीपी योजना में पशु औषधि को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है। 2024-25 और 2025-26 के लिए योजना का

कुल परिय्य 3880 करोड़ रुपए है, जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा तथा दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के वास्ते 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

कर्नाटकमें आईपीएस अधिकारी रूपा का हो गया स्थानांतरण अधिकारी ने फाइल रखने का लगाया था आरोप

बेंगलूरु। (भाषा) कर्नाटक में आईपीएस अधिकारी रूपा डी को बुधवार को आंतरिक सुरक्षा प्रभाग से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया। रूपा डी पर उनकी सहकर्मि वर्तिका कटियार ने अपने (कटियार के) कार्यालय में कथित तौर पर फाइल रखने का आरोप लगाया था।आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, रूपा डी, आईपीएस (2000 बैच), पुलिस महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा प्रभाग को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है और अगले आदेश तक कर्नाटक सिस्लक मार्केटिंग बोर्ड लिमिटेड, बेंगलूरु का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है। वह आईएएस चंद्रशेखर एन. का स्थान लेंगी। पिछले महीने वर्तिका कटियार ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो कनिष्ठ पुलिस अधिकारी उनकी अनुपस्थिति में नियंत्रण कक्ष से चाबियां लेकर उनके कार्यालय में घुस गए। कटियार ने आरोप लगाया कि कनिष्ठ अधिकारियों ने रूपा के कहने पर यह काम किया और उनके कार्यालय में फाइल रख दीं। तीन मार्च को भारतीय पुलिस सेवा की 2010 बैच की अधिकारी कटियार का भी आंतरिक सुरक्षा प्रभाग से स्थानांतरण कर दिया गया था और उन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं अतिरिक्त कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा, बेंगलुरु की पदेन अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात किया गया था। बाद में रूपा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कटियार के आरोपों को झूठा और निराधार बताया। उन्होंने 4 मार्च को लिखे पत्र में कहा, पहली नजर में भी आरोप बेतुके हैं, क्योंकि मैं पदानुक्रम में अगली वरिष्ठ अधिकारी हूं और आधिकारिक तौर पर फाइलों तक मेरी पहुंच है। मैं कोई भी फाइल मंगाना सकती हूं और निस्तारण के बाद वर्तिका कटियार को कोई भी फाइल भेज सकती हूं। ऐसा लगता है कि वह बिना किसी आधार के झूठी कहानी सुना रही हैं। रूपा के अनुसार, कथित घटना 6 सितंबर, 2024 को हुई थी और इन सभी महीनों या अब तक कटियार को कुछ भी गलत या अनुचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि उनके (कटियार) द्वारा विवाद पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से एक बेटुकी और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है।

मिजोरम में विपक्ष की आपत्ति के बाद मद्यपान निषेध संशोधन विधेयकपेश करने का फैसला स्थगित

आइओ।)शराबबंदी वाले राज्य मिजोरम की जोरूम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने विपक्षी दलों की आपत्ति के बाद स्थानीय स्तर पर निर्मित बीयर और वाइन की बिक्री को अनुमति देने वाले विधेयक को बुधवार को विधानसभा में पेश करने का फैसला टाल दिया। मिजोरम शराब (निषेध) अधिनियम या एमएस्पी अधिनियम वाइन और बीयर सहित शराब को बिक्री, निर्माण और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इस कानून को पिछली एमएनएफ सरकार द्वारा 2019 में लागू किया गया था।विधानसभा अध्यक्ष लालबियाकजामा ने कहा कि मिजोरम शराब (निषेध) संशोधन विधेयक, 2025 विपक्षी सदस्यों की अपील के बाद बुधवार को विधानसभा में पेश नहीं किया गया। उन्होंने विधानसभा को सूचित किया कि संशोधन विधेयक को चालू सत्र के दौरान किसी अन्य दिन प्रस्तुत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी एमएनएफ, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने बुधवार को सदन की बैठक से पहले उनसे मुलाक़ात की।

वाला कहा है। पिछले महीने, व्हाइट हाउस

ने प्रधान मंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रम्प ने कहा था कि भारत टैरिफ के मामले में बहुत मजबूत रहा है और मैं उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन यह व्यापार करने का एक अलग तरीका है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास वयावा बाधाएं हैं, बहुत ज्यादा टैरिफ हैं। सद्भावना के संकेत के रूप में, मोदी ने हाल ही में भारत के अनुचित, बहुत ज्यादा टैरिफ में कटौती की घोषणा की थी, जो भारतीय बाजार में अमेरिका की पहुंच को बहुत मजबूती से सीमित करता है और वास्तव में, यह एक बड़ी समस्या है, मुझे कहना होगा। भारत बहुत से सामानों पर 30 से 40 से 60 और यहां तक ​​कि 70 प्रतिशत टैरिफ लगाता है और कुछ मामलों में, इससे कहीं अधिक। उदाहरण के लिए, भारत में जाने वाली अमेरिकी कारों पर 70 प्रतिशत टैरिफ, जो उन कारों को बेचना लगभग असंभव बना देता है। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और मोदी अमेरिकी डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है। मेक्सिको ने कहा कि वह रिवरार को पारस्परिक कारवाई की घोषणा करेगा। चीन ने भी घोषणा की कि वह प्रमुख अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 15 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अतीत में, ट्रम्प ने भारत को टैरिफ किंग और बड़ा दुर्व्यवहार करने

हमें लगता है कि हम वास्तव में इसके हकदार हैं, और वह भी, निष्पक्षता में, इसलिए हम उस पर बहुत मेहनत करने जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अपने अमेरिकी समकक्ष हॉबर्ट लुटनिक के साथ व्यापार वार्ता के लिए वॉशिंगटन में हैं। अमेरिकी अनुमानों के अनुसार, 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कुल माल व्यापार अनुमानित 129.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2024 में भारत को अमेरिकी माल निर्यात 41.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2023 से 3.4 प्रतिशत (1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) अधिक था। भारत से अमेरिकी माल आयात 2024 में कुल 87.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2024 में भारत के साथ अमेरिकी वस्तु व्यापार घाटा 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जो 2023 की तुलना में 5.4 प्रतिशत (2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) अधिक है।

सीबीआई..

पता लगाने के लिए, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों को इकट्ठा करने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच करना आवश्यक है। एक विशेष अदालत ने पत्र अनुरोध जारी करने के लिए सीबीआई यह आदेश को मंजूरी देते हुए कहा था। सीबीआई ने 1990 में मामला दर्ज किया था, तीन साल बाद एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स ने

सौदे को हासिल करने के लिए भारत के राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी थी। आरोपों ने तत्कालीन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया और प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। बोफोर्स घोटाला स्वीडिश बॉफोर्सस के साथ 400 155 मिमी फ़ील्ड हॉवित्ज़र की आपूर्ति के लिए 1,437 करोड़ रुपये के सौदे में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित है। सीबीआई ने 1999 और 2000 में आरोपत्र दायर किए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आत्मघाती हमले में लिट्टे द्वारा उनकी हत्या के लगभग 13 साल बाद 2004 में राजीव गांधी को दोषमुक्त कर दिया था। 2005 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शेष आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई यह साबित करने में विफल रही कि इतालवी व्यवसायी ओतावियो क्रात्रोची द्वारा बोफोर्स द्वारा विभिन्न एजेंटों को हस्तांतरित धन भारत में लोक सेवकों को रिश्वत के रूप में दिया जाना था। सीबीआई ने 2005 के फैसले के खिलाफ 2018 में शीर्ष अदालत में अपील की, लेकिन देरी के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 2005 में अधिवका अजय अग्रवाल द्वारा दायर अपील में सभी बिंदुओं को उठाने की

अनुमति दी।

कनाडा..

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि टूटो ने मंगलवार दोपहर को एक काल में कनाडा के प्रांतों के प्रधानमंत्रियों से कहा कि उन्हें बुधवार को ट्रम्प से बात करने की उम्मीद है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें काल के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। मंगलवार को पहले टूटो सोशल मीडिया पर कहा, ट्रम्प ने कहाँ कृपण कनाडा के गवर्नर टूटो को समझाए कि जब वह अमेरिका पर प्रतियोगात्मक टैरिफ लगाते हैं, तो हमारा पारस्परिक टैरिफ में तुरंत इतनी ही वृद्धि होगी। ट्रम्प ने कनाडा की संप्रभुता को खतरें में डाला है, जिससे देश में गुस्सा भड़क रहा है। हाल ही में एनएचएल और एनबीए खेलों में कनाडाई हॉकी प्रशंसक अमेरिकी राष्ट्रमन्त्र का विरोध कर रहे हैं। टूटो ने कहा, कनाडाई आहत हैं। कनाडाई गुस्से में हैं। हम फ्लोरिडा में छुट्टी पर नहीं जाने का फैसला करने जा रहे हैं।

चीन...

उद्घाटन पर रक्षा वय्य सहित वार्षिक बजट की घोषणा करते हुए चीनी प्रधानमंत्री ली कियान्ग ने पिछले साल कहा था कि चीन ने राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य विकास में बड़ी प्रगति की है। ली ने सत्तारूढ़

नेपाल से लाई जा रही परस जब्त, नेपाली नागरिक गिरफ्तार

बहराइच। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय रूपईडीहा सीमा पर पुलिस व सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने सीमा पार से कथित तौर पर तस्करी कर मनाली ले जाई जा रही चरस बरामद कर एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बुधवार को संवाददाताओं से बताया कि मंगलवार रात पुलिस को सूचना मिली कि नेपाल से बड़ी मात्रा में चरस की खेप आने वाली है। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। इस दौरान रूपईडीहा एसएसबी जांच चौकी पर नेपाल के जिला रोलापा निवासी 50 वर्षीय गौरे घर्ति के कब्जे से नौ किलोग्राम 900 ग्राम चरस बरामद हुई। तिवारी ने बताया कि नेपाली व्यक्ति ने जैकट की आड़ में मांदक पदार्थ को अपने शरीर के अलग अलग हिस्से पर छिपा रखा था। उन्होंने बताया कि बरामद चरस की क्रीमत करीब चार करोड़ रूपए आंकी गई है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए तस्कर से पूछताछ में मालूम हुआ कि नेपाल से लाए गए उक्त मांदक पदार्थ को भात के मनाली (हिमाचल प्रदेश) ले जाया जा रहा था।

अमरनाथ यात्रा तीन जुलाई से

जम्मू। दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर उंचाई पर स्थित अमरनाथ मंदिर के लिए 38 दिवसीय वार्षिक यात्रा तीन जुलाई को शुरू होगी। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में निर्णय रजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (एसएसबी) की 48वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। प्रवक्ता ने कहा, इस साल यात्रा तीन जुलाई को दोनों मार्गों - अनंतनाग जिले में पहलगाम मार्ग और गोंदरबल जिले में बालटाल मार्ग के रास्ते एक राध शुरू होगी और नौ अग्रस्त को रक्षा बंधन पर संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में श्राइन बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया, जिन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव रखा। बैठक में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर और अन्य स्थानों के केंद्रों पर ठहरने को क्षमता बढ़ाने, ई-केवाईसी के लिए यात्री सुविधा केंद्रों का संचालन, आरएफआईडी कार्ड जारी करने, नौगाम और कटरा रेलवे स्टेशनों सहित कई स्थानों पर तीर्थयात्रियों का मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी चर्चा की गई कि आवश्यकता के अनुसार बालटाल, पहलगाम, नुनबान और पंथा चौक श्रीनगर में भी इन सुविधाओं को उचित रूप से बढ़ाया जाए। संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था और अपेक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने श्रीनगर के पंथा चौक स्थित यात्री निवास में क्षमता बढ़ाने के लिए भी कहा। बैठक में लागू की जा रही परियोजनाओं, यात्रा से संबंधित जानकारी का प्रसार, यात्रियों, सेवा प्रदाताओं, खच्चरों को बीमा कवर, श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, यात्रा मार्गों को चौड़ा करने और रखरखाव पर भी चर्चा की गई। प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में गुफा क्षेत्र में भीडभाड कम करने के उपाय, आपदा प्रबंधन की तैयारी, हेलीकॉप्टर सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सा देखभाल सुविधाएं, मौसम पूर्वानुमान बुनियादी ढांचे और सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रेम विवाह करने वाले युवक की भतीजी को किया अगवा, दो आरोपी गिरफ्तार

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में प्रेम विवाह करने वाले एक युवक की भतीजी को उसकी पत्नी के परिजनों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया। पुलिस ने बुधवार को अपहृत लड़कों को पानीपत से बरामद करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश एस. ने बुधवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि जलालाबाद थाना क्षेत्र के जिगनेरा गांव में रहने वाला विकास कुमार पानीपत में रहकर नौकरी करता था, जहां उसका दूसरे धर्म की युवती मुस्कान से प्रेम प्रसंग हो गया। उन्होंने बताया कि विकास 22 फरवरी को मुस्कान को लेकर पानीपत से कहीं और चला गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवती के परिजनों ने इस घटना की पानीपत पुलिस को सूचना नहीं दी क्योंकि दोनों परिवारों के लोग एक-दूसरे के परिचित थे। मंगलवार को मुस्कान के परिजन विकास के गांव जिगनेरा पहुंचे, जहां विवाद के बाद विकास की चार साल की भतीजी कंचन को सबरन कार में बैठाकर ले गए। राजेश ने बताया कि उन्हें मंगलवार शाम को घटना की जानकारी मिली तब उन्होंने तत्काल तीन टीम का गठन करके अलग-अलग मार्ग से पानीपत भेजा और वहां के पुलिस अधीक्षक से बात भी की। पुलिस ने आज पानीपत के आसपास से अगवा की गई बच्ची को मुक्त करा लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि बच्ची के अपहरण के आरोपी जिघाउल तथा उसकी पत्नी हसीना को पुलिस ने पानीपत क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उन्हें पुलिस टीम शाहजहांपुर वापस ला रही है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया है।

अनुशासनहीनता के नोटिस पर पीएसी के कांस्टेबल का अजीबोगरीब जवाब वायरल

मेरठ। मेरठ में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी (पीएसी) के एक कांस्टेबल ने अनुशासन तोड़ने के आरोप में जारी नोटिस पर अजीबोगरीब जवाब देते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी सपने में उस पर हमला करती है और उसका खून पीने की कोशिश करती है, जिससे वह रात को सो नहीं पाता। कांस्टेबल का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।44वीं बटालियन पीएसी के कमांडेंट सचिंद्र पटेल ने बुधवार को पीटीआईभाषा को बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पत्र की प्रामाणिकता, नॉटिस प्राप्त करने वाले कांस्टेबल की पहचान और पत्र के वायरल होने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। यह मामला बटालियन प्रभारी दलनायक मधुसूदन शर्मा द्वारा ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में पीएसी कांस्टेबल को पिछली 17 फरवरी को जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है। नोटिस में कांस्टेबल पर 16 फरवरी को सुबह देर से ब्रीफिंग में पहुंचने, अनुचित तरीके से तैयार होने और यूनिट की गतिविधियों में अक्सर अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था, जिसे अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना गया था। नोटिस के जवाब में, कांस्टेबल ने लिखा कि वह अपनी पत्नी के साथ चल रहे विवादों के कारण अनिद्रा से पीड़ित है। उसने दावा किया कि उसके सपनों में उसकी पत्नी उसकी छाती पर बैठी है और उसे मारने के इरादे से उसका खून पीने की कोशिश करती है जिससे वह सो नहीं पाता है और इसी वजह से वह ब्रीफिंग में देर से पहुंचा। कांस्टेबल ने वायरल पत्र में आगे कहा कि वह अवसाद और चिड़चिड़ेपन के इलाज लिए दवा ले रहा है, और उसकी मां तंत्रिका विकार से पीड़ित है जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई है। कांस्टेबल ने अपनी प्रतिक्रिया को एक भवानत्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त किया। उसने कहा कि उसने जैने की इच्छा खो दी है और खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहता है। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपना दुःख समाप्त करने के लिए आध्यात्मिक मोक्ष का और मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के साथ-साथ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुख्य नेतृत्व पर जोर दिया और सेना पार्टी नेतृत्व का अनुसरण करती है। शी केद्रीय सैन्य आयोग (सीएफसी) के अध्यक्ष भी हैं, जो सभी सेना की उच्च कमान है। उन्होंने कहा, हम लोगों की सशस्त्र सेनाओं पर पार्टी के पूर्ण नेतृत्व के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, केद्रीय सैन्य में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। मंगलवार को पहले टूटो सोशल मीडिया पर कहा, ट्रम्प ने कहाँ कृपण कनाडा के गवर्नर टूटो को समझाए कि जब वह अमेरिका पर प्रतियोगात्मक टैरिफ लगाते हैं, तो हमारा पारस्परिक टैरिफ में तुरंत इतनी ही वृद्धि होगी। ट्रम्प ने कनाडा की संप्रभुता को खतरें में डाला है, जिससे देश में गुस्सा भड़क रहा है। हाल ही में एनएचएल और एनबीए खेलों में कनाडाई हॉकी प्रशंसक अमेरिकी राष्ट्रमन्त्र का विरोध कर रहे हैं। टूटो ने कहा, कनाडाई आहत हैं। कनाडाई गुस्से में हैं। हम फ्लोरिडा में छुट्टी पर नहीं जाने का फैसला करने जा रहे हैं।

घरेलू...

झारखंड पुलिस के साथ वर्ष 2018 और वर्ष 2020 के बीच हुई तीन मुठभेड़ में वह सक्रिय रूप से शामिल थी। पुलिस और नक्सलियों के बीच वर्ष 2018 में कोल्हान में मुठभेड़ हुई। इसके बाद वर्ष 2010 में पोरहाट में और सालक सूचना प्रणाली के विकास में तेजी लाएंगे और चीनी विशेषताओं के साथ आधुनिक सैन्य सिद्धांतों का एक ढांचा स्थापित करेंगे, ताकि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृष्टा से देश की जा सके। एनपीसी के प्रवक्ता लू किनजियान ने मंगलवार कोचीन के बढ़ते रक्षा व्यय का बचाव करते हुए कहा कि शांति को ताकत के साथ सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2016 से चीन के वार्षिक रक्षा व्यय ने लगातार नौ वर्षों तक एफल-अंकीय वृद्धि बनाए रखी है, उन्होंने कहा

औरंगजेब की प्रशंसा करने पर सपा विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित

मुंबई (भाषा)। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली टिप्पणी के कारण बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। आजमी ने उनके साथ नाईसाफ़ी होने का दावा करते हुए कहा कि टिप्पणी वापस लेने के बावजूद उनके खिलाफ यह कार्वाई की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से आजमी की टिप्पणी पर रख स्पष्ट करने को कहा तथा मांग की कि मुगल शासक का महिलामंडल करने के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बुधवार को सदन में शेष अवधि के लिए आजमी के निलंबन का प्रस्ताव

पेश किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा में बयान देना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। पाटिल ने कहा, औरंगजेब की प्रशंसा और संभाजी महाराज की आलोचना करने वाली आजमी की टिप्पणियां एक विधानसभा के सदस्य को शोभा नहीं देती हैं और यह विधानसभा का अपमान है।

सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमा) तक पहुंच गई थी। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक आजमी ने दावा किया था, हमारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) (विश्व जीडीपी का) 24 प्रतिशत थी



और भारत को (औरंगजेब के शासनकाल के दौरान) सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने इसे राजनीतिक लड़ाई करार दिया था। उनकी टिप्पणियों के कारण मंगलवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उन्हें निलंबित

करने और उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। आजमी ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसका जिक्र इतिहासकारों और लेखकों ने किया है। मैंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या किसी भी राष्ट्रीय हस्ती के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। फिर भी, अगर मैंने टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं अपने बयान और टिप्पणियां वापस लेता हूं। आजमी के कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो बयान में आजमी ने मुंबई के मानखुर्द-शिवाजी नगर से विधायक आजमी को शत प्रतिशत जेल में डाला जाएगा। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त

अबू आजमी को जेल में डाला जाएगा: फडणवीस

मुंबई (भाषा)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित किए गए समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आजमी को शत प्रतिशत जेल में डाला जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा-पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। बजट सत्र के समाप्त होने तक विधानसभा से निलंबित किए गए आजमी ने कार्वाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें विवादास्पद टिप्पणी वापस लेने के बावजूद दंडित किया गया है। बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा।

विधान परिषद में जब विपक्ष के नेता और शिवसेना (उबाठा) के सदस्य अंबादास दाने ने फडणवीस से पूछा कि आजमी को उनकी टिप्पणी के लिए जेल क्यों नहीं भेजा गया, तो उन्होंने कहा कि मुंबई के मानखुर्द-शिवाजी नगर से विधायक आजमी को शत प्रतिशत जेल में डाला जाएगा। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त



कार्वाई की जाए। ठाकरे ने मांग की, उन्हें (आजमी को) स्थाई रूप से (विधानसभा से) निलंबित किया जाना चाहिए।

आजमी के कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो बयान में समाजवादी पार्टी के नेता ने दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, लेकिन सदन में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने विधानसभा के बाहर की गई टिप्पणियों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा, फिर भी मुझे निलंबित कर दिया गया। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमा) तक फैली हुई थी। विधायक ने दावा किया, हमारी जीडीपी (विश्व जीडीपी का) 24 प्रतिशत थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा

जाता था। औरंगजेब और मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के बीच लड़ाई के बारे में पूछे जाने पर आजमी ने इसे राजनीतिक लड़ाई करार दिया था। उनकी टिप्पणियों के चलते मंगलवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनके निलंबन और देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की।

बुधवार को यह मुद्दा विधान परिषद में भी उठा, जहां विपक्ष ने अभिनेता रहलु सोलापुरकर और पूर्व पत्रकार प्रशांत कोराटरकर के खिलाफ कार्वाई की मांग की, जो राष्ट्रीय नायकों पर कफित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं। पुलिस ने एक इतिहासकार को धमकी देने और छत्रपति शिवाजी महाराज तथा उनके बेटे संभाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में नागपुर स्थित कोराटरकर पर मामला दर्ज किया है। सोलापुरकर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाई जताप (कांग्रेस) ने कहा कि आजमी द्वारा की गई टिप्पणियों और कोराटरकर तथा सोलापुरकर द्वारा की गई टिप्पणियों से निपटने के लिए अलग-अलग पैमाने नहीं हो सकते। दानव ने (शिवसेना-उबाठा) ने कहा कि सोलापुरकर को पुणे नगर निगम की सांस्कृतिक समिति में नियुक्त किया गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 1931 के शहीदों पर हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने सदन से किया बहिर्गमन

जम्मू(भाषा)। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम रठेर द्वारा 13 जुलाई 1931 के शहीदों पर नेता प्रतिपक्ष की अपमानजनक टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा के सभी 28 सदस्य बुधवार को सदन से बहिर्गमन कर गए। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने 1931 के शहीदों पर यह टिप्पणी उस दौरान की जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक चहरीदुर्हमान पार ने नेशनल कॉंग्रेस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर पांच दिसंबर को पुनः अवकाश देने के साथ-साथ 13 जुलाई को भी सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग की थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने उक्त दोनों छुट्टियों को समाप्त कर दिया था।

उपराज्यपाल के अधिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हुई चर्चा में पार ने ऐसे समय में भाग लिया जब उस दौरान नेशनल कॉंग्रेस (नेका) के अध्यक्ष फरूक अब्दुल्ला सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। पार ने इस दौरान 13 जुलाई, 1931 के बड़े घटना तथा नेका के संस्थापक द्वारा दिए गए योगदान के महत्व का जिक्र करते हुए दोनों अवकाश को पुनः बहाल करने की मांग की। श्रीनगर केंद्रीय कारागार के सैनिकों की गोलीबारी में22 लोगों की जान चली गई थी। पार ने कहा, उन्होंने निरंकुशता के खिलाफ और लोकतंत्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। सदन को, पार्टी संबद्धता और विचारधारा से परे 13 जुलाई की छुट्टी को बहाल करने के लिए एक साथ आना चाहिए और शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को भी उनके राजनीतिक कद और योगदान को देखते हुए बहाल करना चाहिए। पीडीपी विधायक ने बाहरी जेलों से कैदियों को जम्मू-कश्मीर स्वातंत्रािरित करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अनुरोध किया कि वे संपति कुर्क करने तथा अन्य कठोर उपायों के मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाएँ। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल का भाषण लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं तथा नेका के चुनावी वादों को प्रतिबिंबित करने के बजाय भाजपा के एजेंडे के बारे में ज्यदा बता रहा है। भाजपा नेता सुनील शर्मा ने पार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और 13 जुलाई को अवकाश बहाल करने का विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं पार की पार्टी के प्रदर्शन (विधानसभा चुनावों में) के बाद उनके दर्द को समझ सकता हूं। आप महाराज (हरि सिंह) के राज्य का आनंद ले रहे हैं...। यमरा के इस बयान के बाद नेका, पीडीपी सहित निर्दलीय विधायकों ने विरोध जताया तथा दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। माकपा सदस्य एम वाई तारियामी और कांग्रेस नेता निजामुद्दीन भट ने भी 1931 के शहीदों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने तथा नेता प्रतिपक्ष के माफ़ी मांगने की मांग की।

छोटी-सी बात का बतंगड़ बन गया, लेकिन मैं गोवा के खिलाफ नहीं : अबू फरहान आजमी

पणजी (भाषा)। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आजमी के बेटे अबू फरहान आजमी ने गोवा में स्थानीय लोगों के एक समूह के साथ झगड़े को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि एक छोटी-सी बात का बतंगड़ बना दिया गया और वह गोवा के खिलाफ नहीं है। कलंगुट पुलिस थाने के बाहर पीटीआई-भापा से बात करते हुए फरहान ने कहा कि गोवा उनके लिए घर से दूर घर है और उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जो गोवावासियों के खिलाफ है। गोवा पुलिस ने मंगलवार को राज्य में सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने और शांति भंग करने के आरोप में फरहान और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। रेस्तरां मालिक और उद्यमी फरहान पूर्व अभिनेत्री आयाशा टाकिया के पति हैं। फरहान का सोमवार रात गोवा में एक बाइक सवार और उसके साथियों से झगड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, यह एक छोटी-सी बात थी। (जब मैं अपनी गाड़ी को बाढ़ और ले जाना चाहता था) मैंने सिग्नल (इंडिकेटर) दिया था, लेकिन फिर (लोगों के) समूह ने मुझे धक्का दिया, मुझे अपशब्द कहे। फरहान ने बताया कि जब यह घटना हुई, तब वह अपने बेटे के साथ गोवा में मौजूद-मस्ती कर रहे थे। उन्होंने कहा, इसके बाद, वहां भारी भीड़ जुट गई थी और समस्या को भांपते हुए मैंने 100 (पुलिस) नंबर पर फोन किया। चीजें वाकई बहुत उग्र हो गई थीं। फरहान ने हथियार लहराने के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो हथियार लहराए। मैं पिछले 20 साल से गोवा आ रहा हूं।

आईआईटी मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा के लिए ढांचा विकसित किया

नई दिल्ली (भाषा)। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा ढांचा विकसित किया है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के खिलाफ देश में महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है। विकसित किया गया ढांचा बैलिस्टिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए अभिनव समाधान तैयार करने में मदद करेगा। अनुसंधान के निष्कर्ष प्रतिष्ठित पत्रिका रिटाइएबिलिटी इंजीनियरिंग एंड सिस्टम सेफ्टी में प्रकाशित हुए हैं। कम्प्यूटेशनल सिमुलेशन का उपयोग करते हुए अनुसंधानकर्ताओं ने आरसी पर मिसाइलों के प्रभाव का अध्ययन किया।

तेजस्वी ने बिहार में 100% मूल निवास नीति लागू करने का वादा किया

पटना (भाषा)। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो बिहार में सौ प्रतिशत मूल निवास (डोमिसाइल) नीति लागू की जाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री पटना में एक युवा पंचायत को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राज्य के लोगों के बीच सरकारी नौकरियों के प्रति प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कई वादे किए। यादव ने पूछा, क्या बिहार में डोमिसाइल नीति होनी चाहिए। इस पर, भीड़ ने हां कहा, तो राजद नेता ने कहा, हम राज्य के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सौ प्रतिशत मूल निवास नीति लागू करने के प्रयास तकनीकी कारणों से विफल हो गए। लेकिन मैंने कई न्यायविदों से इस मामले पर चर्चा की है और हमने इसका समाधान खोज लिया है। यादव ने आरोप लगाया कि 74 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक गए हैं और उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। राजद नेता ने आरोप लगाया कि कुमार की सहयोगी आरक्षण खोर भाजपा आरक्षण को बैसे ही खा जाती है जैसे आदमखोर होते हैं।

यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन राज्य में अगली सरकार बनाएगा, यादव ने कहा, हम एक युवा आयोग का गठन करेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे आग्रह पर ही सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू हुई हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हम सत्ता में थे। अपनी सरकार बनने पर हम और अधिक भर्तियां करेंगे। यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली फीस माफ करेगे। साथ ही कहा कि उम्मीदवारों का परिवहन व्यय, जिन्हें अक्सर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यादव ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर राजद वंचित जातियों के लिए आरक्षण में वृद्धि को पुनः बहाल करने का प्रयास करेंगे, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। यादव ने दावा किया कि पिछले कुछ चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी राजद के पास सबसे अधिक युवा सौंदर्य और विधायक हैं और इसलिए वह बिहार की युवा आबादी की आकांक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।



कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय में वेद ज्ञान सप्ताह के दौरान प्रतिगान करते विद्यार्थी

तेजस्वी ने बिहार में 100% मूल निवास नीति लागू करने का वादा किया



अपने भाई तेजप्रताप के साथ तेजस्वी यादव

मैं ने नीतीश को दो बार मुख्यमंत्री बनाकर बचाया, वरना उनकी पार्टी खत्म हो जाती : तेजस्वी
पटना (भाषा)। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद पर बने रहने और जनता दल (यूनाइटेड) को टूटने से बचाने में दो बार मदद की। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी मंगलवार को

आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 से

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक 21 से 23 मार्च तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी, जिसके एजेंडे में हिंदू जागरण का मुद्दा भी शामिल है। संगठन ने एक बयान में कहा कि बैठक में इस साल चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मुद्दों पर दो प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए (बैठक में) विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही संघ की शाखाओं से जैसी अपेक्षा रही है, सामाजिक परिवर्तन के कार्यों, विशेष रूप से पंच परिवर्तन के प्रयासों पर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। बयान के अनुसार आरएसएस के पंच परिवर्तन का लक्ष्य है भारतीय मूल्यों के साथ स्व की भावना जागृत करना, पारिवारिक मूल्यों को आत्मसात करना, सामाजिक सौंदर्य को बचाए देना, लोगों में पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने और नागरिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। बैठक में सरसंघचालक मोहन भगवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले तथा सभी सह सरकार्यवाह एवं अन्य पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहें।।

सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण की योजना बना रही है कांग्रेस: भाजपा

बेंगलुरु (भाषा)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की योजना बना रही है। कर्नाटक की भाजपा इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने दावा किया कि जब राज्य भर में सभी विकास कार्य थम गए हैं, तब राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश करने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कई अन्य समुदाय होने के बावजूद अल्पसंख्यकों को हमेशा मुसलमान के तौर पर संदर्भित क्यों किया जाता है। विजयेंद्र ने यहां संबाददाताओं से कहा, क्या अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होना चाहिए कोई और नहीं? कांग्रेस की अल्पसंख्यक टुट्टिकरण की नीतियां समाज में अशांति पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वाकई पिछड़े समुदायों के नेता हैं, जैसा कि वे खुद को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें, उनको सशक्त बनाने के लिए नीतियां लानी चाहिए। विजयेंद्र ने लोगों से सिद्धरमैया को उनकी अल्पसंख्यक टुट्टिकरण नीति के लिए सबक सिखाने की अपील की। विजयपुर के विधायक बसगांड़ु पाटिल यतनाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यक टुट्टिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इस तरह का आरक्षण संविधान विरोधी है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय संविधान के निर्माता बी आंबेडकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के खिलाफ थे। यतनाल ने आरोप लगाया, सरकार संविधान और उच्च न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ जा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को कर्नाटक विधानसभा के मौजूदा सत्र में उठाएंगे।

लोकसभा परिसीमन : स्टालिन ने सांसदों की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाने का प्रस्ताव रखा

चेन्नई (भाषा)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र पर दबाव बढ़ाते हुए बुधवार को प्रस्ताव दिया कि 1971 की जनगणना को 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनाया जाए। उन्होंने इसी के साथ सभी दक्षिणी राज्यों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) का गठन रखने का प्रस्ताव किया। स्टालिन ने परिसीमन पर यहां एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य विपक्षी दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कर्घम (अन्नाद्रमुक) सहित अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि की स्थिति में, 1971 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाना चाहिए और इसके लिए उचित संविधान संशोधन किया जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि इसके अलावा 1971 की जनगणना के आंकड़ों को 2026 से अगले 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीटों के परिसीमन का आधार बनाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इसका आक्षसन देना चाहिए। स्टालिन द्वारा पेश प्रस्ताव के मुताबिक, जेएसी ऐसी मांगों को आगे बढ़ाएगी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेगी। बैठक में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया का सर्वसम्मति से विरोध किया गया और कहा गया कि यह संघवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दक्षिणी राज्यों के अधिकारों के लिए खतरा होगा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि संसद में तमिलनाडु का वर्तमान प्रतिनिधित्व 7.18 प्रतिशत है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाना चाहिए। बैठक में इंके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सहित अन्य दलों के समर्थन से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें केंद्र से इस मुद्दे पर तमिलनाडु की मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। बैठक में रेखांकित प्रमुख बिंदुओं में से एक यह था कि लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं की जाए। बैठक में रेखांकित किया गया कि तमिलनाडु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ नहीं है। हालांकि, प्रस्तावित प्रक्रिया को पिछले 50 वर्षों के दौरान सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपायों को अच्छी तरह से लागू करने की सजा नहीं साबित होना चाहिए। बैठक में कहा गया कि केंद्र ने उस राज्य की आवाज सुनने से इनकार कर दिया, जिसके 39 लोकसभा सदस्य हैं। इसमें कहा गया कि अगर यह संख्या कम कर दी गई, तो राज्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक इस बात को समझने के लिए है कि परिसीमन के मुद्दे पर राज्य को हाशिए पर धकेल दिया गया है, जिससे उसे अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्टालिन ने आरोप लगाया, दक्षिण भारत के सिर पर परिसीमन की तलवार लटक रही है और तमिलनाडु इससे बुरी तरह प्रभावित होगा। अन्नाद्रमुक, कांग्रेस, वामपंथी दल और अभिनेता से नेता बने विजय को तमिलना वेट्टी कणगम (टीवीके) सहित अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। जबकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), नाम तमिलर काची (एनटीके) और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन की तमिल मनीला कांग्रेस (मूणनार) ने बैठक का बहिर्कार किया।

सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कणगम (द्रमुक) परिसीमन की कवायद का कड़ा विरोध कर रही है। पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री स्टालिन का दावा है कि इससे तमिलनाडु में लोकसभा की सीट कम हो जाएगी। उन्होंने सवाल किया है हैं कि क्या राज्य को पिछले कुछ साल में जनसंख्या नियंत्रण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दंडित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों को प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने स्टालिन पर इस मामले पर गलत सूचना अभियान चलाने का आरोप लगाया था। अटकलों पर विराम लगाते हुए शाह ने कहा था कि जब आनुपातिक आधार पर परिसीमन किया जाएगा, तो किसी भी दक्षिणी राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आएगी। तमिलनाडु के अलावा कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों क्रमशः सिद्धरमैया और ए रेवंत रेड्डी ने भी परिसीमन पर शाह के बयान पर सवाल उठाए हैं।

महाकुंभ में नाविकपिटू महरा के परिवार ने कमाए 30 करोड़ रुपए

प्रयागराज (भाषा)। प्रयागराज महाकुंभ ने ऑटो चालकों, खान पान की दुकान लगाने वालों से लेकर नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। ऐसे ही एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विधानसभा में सुनाई। प्रदेश सरकार के मुताबिक, प्रयागराज के अरैल इलाके में रहने वाले नाविक पिटू महरा का परिवार करोड़पतियों की कतार में शामिल हो गया। पिटू महरा का कहना है कि उन्होंने 2019 के कुंभ में नाव चलाई थी और उन्हें अनुमान था कि इस बार महाकुंभ में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उठाने वाली है। पिटू महरा के परिवार ने महाकुंभ के पहले 70 नावें खरीदीं। पहले से उनके सौ से अधिक सदस्यों वाले परिवार में 60 नावें थीं। इस तरह इस 130 नावों को महरा परिवार ने महाकुंभ में उतार दिया। पिटू महरा और उनके परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आयोजित हुए इस महाकुंभ (की व्यवस्थाओं) ने उनकी ही नहीं, बल्कि हजारों नाविक परिवारों की जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि जिन नाविकों ने कर्ज लेकर नावें खरीदीं, वो सब अब लखपति बन गए हैं। पिटू की मां शुक्लवती देवी यह बताते हुए भावुक हो गईं कि उनके पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूरा परिवार परेशान था। उन्होंने कहा कि ऐसे में महाकुंभ उनके लिए संकट मोचक बनकर आया।

ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई: जयशंकर

हवाई में ज्वालामुखी से लावा फूटा, 150 फुट से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा

भाषा। लंदन
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन में उनके समकक्ष डेविड लेमी के साथ उनकी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें पुनः शुरू की गई मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता, रणनीतिक समन्वय और राजनीतिक सहयोग शामिल है। लेमी ने जयशंकर की मेजबानी की। केंट के शेर्वेनिंग हाउस में दो दिन तक हुई व्यापक और सार्थक वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। बंद कर्मों में हुई बैठकों से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों विदेश मंत्री 17वीं सदी के कंटी हाउस का दौरा करते और मैदान के चारों ओर टहलते हुए गहन बातचीत करते दिखाई देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर



वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के शेर्वेनिंग हाउस पहुंचे, जहां उनका मंत्री जयेशी से स्वागत किया गया।

भारत के शेर्वेनिंग स्कॉलर्स के लिए लेमी द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के बाद जयशंकर ने कहा, हमारी प्रतिभा और लोगों के बीच आदान-प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति, वे निश्चित रूप से भारत-ब्रिटेन संबंधों की महान समर्थक हैं। वार्ता का स्थान दुनिया के सबसे बड़े शेर्वेनिंग कार्यक्रम-ब्रिटेन सरकार की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना के केंद्र के रूप में भारत की स्थिति का प्रतीक था। लेमी ने वार्ता से पहले विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा, दिल्ली में व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने के बाद डॉ. जयशंकर और मैं भारत के साथ हमारे 41 अरब जीवोपी के व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह हमारी महत्वाकांक्षाओं की सीमा नहीं, बल्कि मंजिल है जिससे हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

दूतावासों का उद्घाटन करेंगे। लेमी ने कहा, बेलफास्ट और मैनचेस्टर में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का खुलना हमारे लोगों के बीच बढ़ते संबंधों को दर्शाता है और हम न केवल लंदन में, बल्कि पूरे ब्रिटेन में प्रगति की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। बाद में बुधवार को, जयशंकर लंदन में रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में दुनिया में भारत का उदय और भूमिका शीर्षक पर एक वार्तालाप सत्र में भी भाग लेंगे। इस संस्थान को आमतौर पर चैथम हाउस के नाम से भी जाना जाता है।

संबंधित थिंक टैंक के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी ब्रान्वेन मैडॉक्स कई विषयों पर जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। इसमें विदेश नीति संबंधी भारत के दृष्टिकोण और यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया और प्रमुख वैश्विक बिंदुओं पर भारत की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

इजराइल के गाजा में खाद्य व सहायता आपूर्ति रोकने से लोगों के सामने संकट फिर खड़ा हुआ

यरुशलम। (एपी) इजराइल ने गाजा की 20 लाख की आबादी के लिए खाद्य, ईंधन, दवाएं और अन्य आपूर्ति रोक दी है जिससे कीमते बढ़ गई हैं तथा मानवीय सहायता समूह शेष भंडार को सबसे कमजोर लोगों तक वितरित करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। सहायता पर रोक से सहायताकर्मियों की वह प्रगति खतरे में पड़ गई है जो उन्होंने पिछले छह सप्ताहों में इजराइल और हमवास के बीच जनवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते के प्रथम चरण के दौरान भूखमरी से निपटने के लिए हासिल की थी। करीब सोलह महीने के युद्ध के बाद, गाजा की आबादी पूरी तरह से बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री और अन्य सहायता पर निर्भर है। ज्यादातर लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और कई लोगों को आश्रय की जरूरत है। अस्पतालों, पानी के पंपों, बैकरीयों और दूरसंचार के साथ ही सहायता पहुंचाने वाले ट्रकों को चालू रखने के लिए ईंधन की जरूरत है। इजराइल का कहना है कि घेराबंदी का उद्देश्य हमवास पर उसके युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना है। इजराइल ने हमवास के साथ हुए समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़ने में देरी की है, जिसके दौरान राहत सामग्री की आवाजाही जारी रहनी चाहिए थी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने मंगलवार को कहा कि वह दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं और अगर हमवास नहीं सुकता है तो वह गाजा की बिजली काटने से भी नहीं हिचकेंगे।

सुनीता विलियम्स सहित नासा के दो अंतरिक्ष यात्री नौ महीने बाद आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं

केप कैनावेरल। (एपी) नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के दो अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता (सुनी) विलियम्स अंतरिक्ष में नौ महीने बिताने के बाद आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं। बुच विल्मोर और भारतीय मूल की विलियम्स को अगले सप्ताह तक उनकी जगह अन्य अंतरिक्ष यात्री के आने तथा उसके अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने तक इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वे इस महीने के अंत में अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकल सकेंगे।



वे अपने स्पेसएक्स राइड होम में दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शामिल होंगे। मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान विल्मोर ने कहा कि राजनीति जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसने उनकी और विलियम्स की वापसी में कोई भूमिका नहीं निभाई। हालांकि, स्पेसएक्स कैप्सूल

उत्तर में मस्क के हाल के उस आव्हान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने 2031 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कक्षा से बाहर निकालने के नासा के प्रस्तावित डिऑर्बिट अभियान की प्रतीक्षा करने के बजाय, दो वर्षों में ही अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने की बात कही थी। उन्होंने परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला में किए जा रहे सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का उल्लेख किया। डिऑर्बिट करने की योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से लाकर उसे पूरी तरह से जला देना और मलबे को महासागर में गिराना शामिल है।

विलियम्स ने कहा, यह जगह बहुत बढ़िया है। यह वाकई अद्भुत है, इसलिए मैं कहूंगी कि हम अभी अपने चरम पर हैं। विलियम्स तीन बार अंतरिक्ष स्टेशन में रह चुकी हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अभी शायद यह

पाकिस्तान में सैन्य अड्डे के पास बम विस्फोट में मारे गए 12 लोगों के जनाजे की नमाज अदा की गई



पेशावर। (एपी) पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक दिन पहले सैन्य अड्डे की निशाना बनाकर किए गए दोहरे बम विस्फोट में मारे गए 12 लोगों का अंतिम संस्कार करने की तैयारियों के बीच, बुधवार को अंतिम रस्ते पर दुकानें बंद रह गईं। प्रांत के बन्नु शहर में मंगलवार की शाम हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान से जुड़े एक चरमपंथी संगठन ने ली है। इन दो आत्मघाती हमलों के जरिए सैन्य अड्डा परिसर की चहारदीवारी तोड़ दी गई थी। हमले के वक्त, कई स्थानीय निवासी इपतार कर रहे थे या निकट की एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। विस्फोटों के बाद, अन्य हमलावरों ने सैन्य अड्डा परिसर में धावा बोल दिया और सैनिकों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। विस्फोट के कारण मस्जिद की भी भारी नुकसान पहुंचा। हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि हमले या उसके बाद हुई मुठभेड़ में कितने सुरक्षा कर्मी मारे गए या घायल हुए हैं। बन्नु समुदाय के एक बुजुर्ग सदस्य आलम खान ने बताया कि इलाके के एक खेल परिसर में जनाजे की नमाज अदा की गई। खान ने कहा, सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। अधिकतर दुकानें भी बंद हैं। उन्होंने बताया कि बचावकर्मियों ने विस्फोट में ढही मस्जिद के मलबे से तीन नमाजियों के शवों को निकाला है। बन्नु, अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और वहां कई हथियारबंद समूह सक्रिय हैं। पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े एक समूह जैश अल-फुरसान ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

अमेरिका के फ्लोरिडा में भारतीय मूल की नर्स पर मरीज ने किया हमला

ट्यूस्टन (अमेरिका)। (भाषा) अमेरिका में फ्लोरिडा के एक अस्पताल में भारतीय मूल की एक नर्स पर एक मरीज ने हमला कर दिया। आरोपी मरीज ने 67 वर्षीय नर्स के चेहरे पर कई बार घूंसा मारा जिससे उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। स्थानीय मीडिया ने इस बारे में खबर दी। पुलिस ने बताया कि नर्स लीला लाल को लीलाम्मा लाल के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पाम्प वेस्ट हॉस्पिटल के मनोरोग वार्ड में 18 फरवरी को 33 वर्षीय मरीज स्टीफन एरिक स्कैटलबरी ने लीलाम्मा लाल पर हमला किया जिससे उनके चेहरे की हर हड्डी टूट गई। समाचार चैनल डब्ल्यूपीटीवी डॉट कॉम के अनुसार, स्थानीय अदालत में एक पुलिस अधिकारी ने गवाही दी कि एक वीडियो क्लिप में स्कैटलबरी यह कहते हुए दिखा रहा है, भारतीय बुरे हैं और मैंने अभी-अभी एक भारतीय डॉक्टर को पीटा है। समाचार चैनल ने बताया कि स्कैटलबरी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और उस पर घृणा अपराध बढ़ाने का भी आरोप है। अगर वह दोषी पाया जाता

शरीफ ने पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया

इस्लामाबाद। (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आतंकवाद रोधी प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करने और उसकी सरहना करने के लिए बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने मोहम्मद शरीफुल्ला उर्फ जफर की गिरफ्तारी में मदद करने के लिए पाकिस्तानी सरकार को धन्यवाद दिया है। शरीफुल्ला ने 2021 में एबी गेट हमले सहित कई घातक हमलों के लिए आईएसआईएस-के की ओर से गतिविधियों का समर्थन और संचालन किया था। हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एचकेआईए) पर 26 अगस्त, 2021 को हमला उस समय हुआ था, जब अमेरिकी और अन्य गठबंधन सैन्य बल अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियान को समाप्त करने के

तहत हवाई अड्डे पर निकासी अभियान संचालित कर रहे थे। हमला तालिबान द्वारा कानुल पर नियंत्रण हासिल करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। शरीफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आतंकवादी एक अफगान नागरिक हैं और उसे अफगानिस्तान की सीमा पर एक अभियान में पकड़ा गया है। शरीफ ने कहा, हम क्षेत्र में आतंकवाद रोधी प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका और समर्थन को स्वीकार करने और उसकी सरहना करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं, जिसका संदर्भ हाल ही में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा आईएसकेपी के शीर्ष स्तर के कमांडर शरीफुल्ला को पकड़े जाने से है, जो एक अफगानिस्तानी नागरिक है इन्होंने

दक्षिण सूडान: सेना ने उपराष्ट्रपति के घर के घेरा, उनके सहयोगियों के गिरफ्तार किया

जुबा। दक्षिण सूडान के सैनिकों ने बुधवार को राजधानी में उपराष्ट्रपति रीक माचर के घर को घेर लिया और उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटनाक्रम देश के उत्तर में स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान पर माचर से संघर्ष एक सशस्त्र समूह द्वारा हमला किए जाने के बाद हुआ। राष्ट्रपति साल्वा कीर के साथ माचर की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अंततः में गृहयुद्ध में बदल चुकी है। माचर ने पिछले महीने कहा था कि सरकार में पदों से उनके कई सहयोगियों को हटाए जाने से उत्तेजित और कीर के बीच 2018 के शांति समझौते को खतरा पैदा हो गया है। शांति समझौते के तहत पांच साल से जारी गृहयुद्ध पर विराम लग गया था जिसमें चार लाख से अधिक मारे गए हैं।

ग्रीनलैंड हमारा है, इसे खरीदा नहीं जा सकता: ट्रंप के संदेश के जवाब में द्वीप के प्रधानमंत्री ने कहा

नुऊक (ग्रीनलैंड)। (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदेश को तबज्जो न देते हुए ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मुटे बोरुप एग्डे ने बुधवार को कहा कि ग्रीनलैंड हमारा है और इसे खरीदा नहीं जा सकता। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन आर्कटिक द्वीप के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका को इस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके खुद के लोग तय करेंगे। उनका यह पोस्ट मंगलवार को संसदीय चुनाव के लिए द्वीपवासियों के मतदान करने से एक सप्ताह पहले ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंडवासियों से की गई अपील के बाद आया। ट्रंप ने कहा था, हम अपना भविष्य निर्धारित करने के आपके अधिकार का पुर्जोर समर्थन करते हैं और यदि आप चुनते हैं, तो हम अमेरिका में आपका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। हम आपको अमीर बनाएंगे। और हम सब मिलकर ग्रीनलैंड को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। ट्रंप ने लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे डेनमार्क से ग्रीनलैंड हासिल करने की अपनी इच्छा का जिक्र किया और कहा कि उनका प्रशासन इसे हासिल करने के प्रयास में शामिल सभी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय विश्व सुरक्षा के लिए हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम इसे हासिल करने जा रहे हैं। किसी न किसी तरह, हम इसे हासिल करने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड एक विशाल और खनिज-समृद्ध द्वीप है। यह डेनमार्क का अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र है और इसके अनेक लोग इस पर कब्जा करने की टुंगी की धमकियाँ से चिंतित एवं आहत हैं।

संकेत मिले हैं कि रूस शांति के लिए तैयार, यूक्रेन

न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। (भाषा) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस से मजबूत संकेत मिले हैं कि वह शांति के लिए तैयार है, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि उनका देश वार्ता की मेज पर आने और खनिज एवं सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यह बात मंगलवार रात काँग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन में जारी भीषण संघर्ष को समाप्त करने के लिए भी अथक प्रयास कर रहा हूँ। इस भीषण और क्रूर संघर्ष में लाखों यूक्रेनी और रूसी बेवजह मारे गए या घायल हुए हैं। इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मंगलवार को जेलेन्स्की का पत्र मिला जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन स्थाई शांति के लिए जल्द से जल्द बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार है। सबसे अधिक यूक्रेन के लोग शांति चाहते हैं। उनके अनुसार, जेलेन्स्की ने पत्र में लिखा है कि वह और उनकी टीम स्थाई शांति पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मजबूत



नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। हम वास्तव में इस बात की सरहना करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने, उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए

कितना कुछ किया है। खनिजों और सुरक्षा पर समझौते के संबंध में, यूक्रेन किसी भी समय उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। ट्रंप ने कहा कि वह पत्र की सरहना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा हमने रूस के साथ गंभीर चर्चा की है और मुझे मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं। क्या यह ठीक नहीं होगा? उन्होंने कहा, ... यह

काबुल हवाई अड्डे पर 2021 में हुए हमले के जिम्मेदार आतंकी को अमेरिका लाया जा रहा : ट्रंप

न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगस्त 2021 में अमेरिकी बलों की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर बम विस्फोट करने के जिम्मेदार शीर्ष आतंकवादी को पकड़ लिया गया है तथा उसे इस्लाम कट्टरपंथी से खड़ा करने के लिए बंध लाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि साढ़े तीन साल पहले, आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान से विनाशकारी और अश्वन वापसी के दौरान एबी गेट पर बम विस्फोट किया था जिससे 13 अमेरिकी सैनिकों और अनिश्चित अन्य लोगों की मौत हो गई थी। ट्रंप ने मंगलवार रात वॉशिंगटन (संसद) के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका एक बार फिर कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की ताकतों के खिलाफ जगभूरी से खड़ा है। यह खतरा हमसे उनके दूरसे कार्यवाहक का पहला सत्र था। सीएफएन की एक टाइटल को क्या गया है कि क्या ट्रंप हउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि हमले की साक्षि ने उचित रूप से शामिल मोहम्मद शरीफुल्ला को अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा, ऐसा नहीं है कि वे वापस आ रहे थे, बल्कि उनसे पहले वे वापस आ रहे थे, वह शर्मनाक था। शायद यह हमारे देश के इतिहास का सबसे दर्दनाक क्षण था। राष्ट्रपति ने कहा, आज रात, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है रही है कि हमने उन अत्याचार के लिए जिम्मेदार शीर्ष आतंकवादी को पकड़ लिया है और यह अब अमेरिकी न्याय का सामना करने के लिए लाया जा रहा है। ट्रंप ने इस राक्षस को गिरफ्तार करने में मदद करने के लिए पाकिस्तान सरकार को धन्यवाद दिया।

पागलपन रोकने का समय है। यह हत्या रोकने का समय है। यह निरर्थक युद्ध को समाप्त करने का समय है। यदि आप युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको दोनों पक्षों से बात करनी होगी। ट्रंप के

संबोधन के कुछ घंटों पहले जेलेन्स्की ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह दीर्घकालिक शांति के लिए ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार है।

